



04 - ईरान में सता संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और भारत की चिंता



05 - मानवीय सवालों की सुनामी में बढ़ती समाधान शून्यता!



06 - गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद...



07 - मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना से आत्मनिर्भर बनीं...

कड़वा

प्रसंगवश

अब परिवारवाद पर भी पलटी मार गए हैं नीतीश कुमार?

समी अहमद

नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पापा की पार्टी में एक-दो दिन में शामिल हो जाएंगे और फिर इस पर बहस चलेगी कि वह किस हद तक जेडीयू को संभाल पाएंगे। अपनी पलटीमार विचारधारा के लिए चर्चित रहे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जाते-जाते एक और पलटी मारी और परिवारवाद के विरोध के नाम पर लालू प्रसाद का दुश्मनी की हद तक विरोध शुरू करवा कर औपचारिक रूप से धराशायी हो गया। इससे पहले वह कई बार सरकार बनाने के लिए पार्टियों के साथ आने और पार्टियों का साथ छोड़ने के दौरान पलटी मारते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी माने जाने वाले मुद्दों पर भी उन्होंने समझौता ही किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि विचारधारा से समझौता ही उनकी विचारधारा रही।

नीतीश कुमार के 'नेतृत्व' में पार्टी के विधायकों और सांसदों और दूसरे नेताओं की बैठक हुई जिसमें औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया जाए और नीतीश कुमार को इस पर 'सहमति' भी ले ली गई। इस बात पर भी बहस हो सकती है कि यह बैठक किस हद तक उनके 'नेतृत्व' में हुई और 'सहमति' किस हद तक उनकी अपनी है।

इस बैठक से निकलने के बाद निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करवाने के लिए अपनी बेचैनी जताते रहे नेताओं ने यह बताया कि फिलहाल निशांत कुमार कोई पद नहीं लेंगे लेकिन पदयात्रा यानी दौरा करेंगे। ऐसे में यह बात याद रखने की है कि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष रहते हुए और नहीं रहते हुए भी

एक और पद पर रहते थे और उस पद का नाम था 'सर्वमान्य नेता'। तो शायद फिलहाल निशांत कुमार को भी जदयू के सर्वमान्य नेता का पद मिल जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या पापा की पार्टी में शामिल होने वाले निशांत कुमार पापा की पार्टी को संभाल भी पाएंगे? यह वही निशांत कुमार हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को छोड़कर किसी को यह नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी 49-50 साल की उम्र के दौरान उन्होंने क्या किया।

हाल में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई थी कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिलहाल केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें एक महंगा प्लैट गिफ्ट में दिया था। इसके अलावा उनकी चर्चा पूजा पाठ और दूसरी आध्यात्मिक बातों के लिए होती थी।

हालांकि एक बात जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई वह इसका संकेत देती है कि निशांत कुमार को सरकार में क्या हैसियत हासिल थी। कुछ दिनों पहले निशांत कुमार गयाजी के दौर पर थे और वहां उनके साथ अधिकारियों की टीम भी चल रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि आधिकारिक ना होते हुए भी निशांत कुमार को अधिकारियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।

बहरहाल, राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि भले ही जदयू के नेताओं को ऐसा लगता हो कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी को संभाल लेंगे लेकिन अनुभव की कमी के अलावा उनके पास राजनीति की चाल समझने की क्षमता पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

इस बात की चर्चा भी बहुत कम होती है लेकिन

यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार और उनकी पत्नी के बीच के कड़वाहट भरे रिश्ते का उनके पुत्र निशांत कुमार पर नकारात्मक असर देखा जा सकता है। कई लोग इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि निशांत कुमार अपने पिता से भी एक अजनबी की तरह ही मिलते रहे हैं हालांकि हाल के दिनों में दोनों की मुलाकात पर चर्चा भी हुई है। लेकिन जब एक पिता-पुत्र की मुलाकात भी खबर बन जाए तो इससे इस पूरे मामले को समझना आसान हो सकता है।

निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने से शायद सबसे ज्यादा खुशी तेजस्वी यादव को होगी जो शुरू से कहते रहे हैं कि वह उनका राजनीति में स्वागत करेंगे। तेजस्वी पहले ही परिवारवाद के आरोपी को खोखला साबित करने के लिए जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट जारी करते रहे हैं जो अपने परिवार की वजह से राजनीति में आए हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा है। अब तो नीतीश कुमार को भी इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं बचेगा। हालांकि इस बात में शक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी कोई नैतिकता दिखाएंगे और वह तेजस्वी पर परिवारवाद के लिए हमले न करें।

तेजस्वी शायद इस बात से भी खुश हो रहे होंगे कि अगर निशांत कुमार जदयू की कमान संभालते हैं तो उनको उस तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसी चुनौती नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान राजद को मिलती रही है। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा है कि निशांत कुमार की अनुभवहीनता और अपरिपक्वता के कारण जेडीयू में गुटबाजी बढ़ेगी।

इस पूरे मामले में जेडीयू के बड़े लीडर भी वैचारिक रूप से बेपर्दा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बहना यह निकाला है कि निशांत युवा हैं और राजनीति में बेहतर कर सकते हैं। इस मामले में नीतीश से बेहतर उंपेंद्र कुशवाहा को माना जा सकता है जिन्होंने साफ तौर पर परिवारवाद को पार्टी बचाने के लिए जर्करी माना है। एक तरह से उंपेंद्र कुशवाहा ने यह स्वीकार किया कि हां, उनकी पार्टी की विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ नहीं है और चुपचाप अपने बेटे को बिना कोई चुनाव जीते मंत्री बनवा लिया।

इस मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केशी त्यागी का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने हमेशा नीतीश कुमार की पलटीमार विचारधारा का समर्थन किया, उसके लिए बेमतलब तर्क गढ़े और लालू प्रसाद को अपने बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने पर परिवारवादी कहकर आलोचना का शिकार बनाया। शायद इससे भी बड़ी बात यह हो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ने जिस तरह लालू के परिवारवाद का विरोध किया वह भी इस मामले में पलटीमार विचारधारा के समर्थक ही साबित हुए।

वैसे तो परिवारवाद पर बोलने का अधिकार पहले भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, क्योंकि इससे पहले ही परिवारवादी पॉलिटेक्स का वह समर्थन करते रहे, बस शर्त यह रही कि ऐसे परिवार उनकी पार्टी में हों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी में नहीं। भारत की राजनीति में परिवारवाद का विरोध जितना मूर्ख बनाने वाला तर्क शायद ही कोई और हो।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subhasaverenews@gmail.com
facebook.com/subhasaverenews
www.subhasavere.news
twitter.com/subhasaverenews

एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा ईरान

● कहा-जो देश इजराइल-अमेरिका के राजदूतों को निकालेंगे सिर्फ उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर रखी एक नई शर्त



तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वह एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजराइली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल

और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं।

● 180 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित - रॉयटर्स के मुताबिक नासिर ने कहा कि इस लड़ाई के कारण अब तक 180 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल इकोनमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। पिछले सत्र में यह 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था जो इसका तीन साल का उच्चतम स्तर है। हालांकि आज इसमें 10 फीसदी तक गिरावट आई है। नासिर ने कहा कि होर्मुज की खाड़ी को बाइपास करने के लिए कंपनी के पास के केवल एक ही विकल्प ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन है। इससे रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल भेजा जा सकता है। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन से ज्यादा से ज्यादा तेल भेजा जाएगा क्योंकि लॉडिंग टर्मिनल्स पर ज्यादा करस्टमर आ रहे हैं।

सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे

● सुप्रीम कोर्ट बोला-जल्द से जल्द एएर-फ्री पॉलिसी बनाए



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है।

कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम को मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की आगामी 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33 हजार 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। सिंगरौली के चितरंगी में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित कुल 7 नवीन पदों के सृजन की भी मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने मैहर, कैमोर जिला कटनी और निमरानी जिला खरगोन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी है।



मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम को 3 वर्ष क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रुपये की स्वीकृति - मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम को 3 वर्ष के लिए क्रियान्वयन के लिए लगभग 190 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अग्रिम कार्यवाही तथा प्रक्रिया निर्धारण कर नियमों एवं निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है।

निःशक्त जन को वृत्तिकर से छूट की निरंतरता की स्वीकृति - मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्त जन को वृत्तिकर से छूट को 31 मार्च,

सिंगरौली में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित 7 पदों की स्वीकृति - मंत्रि-परिषद ने चितरंगी जिला सिंगरौली में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का एक नवीन पद और उनके कार्यालयीन अमले के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 नवीन पद सहित कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

2030 तक निरंतर किये जाने की स्वीकृति दी गयी गई है।

7 जिलों के लिए एक जिला-एक उत्पाद परियोजना का अनुमोदन - मंत्रि-परिषद द्वारा एक जिला-एक उत्पाद परियोजना अंतर्गत चयनित 07 जिलों में पारंपरिक व विशिष्ट उत्पाद के संरक्षण, विकास और विपणन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगामी 5 वर्षों में 37.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना में चयनित 07 जिलों में सीधो जिले में दरी एवं कारपेट,

दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी, हाथकरवा वक्त्र, भोपाल में जरी-जरदोजी एवं जूट उत्पाद (जैसे पर्स आदि), धार में बाग फ्रिट, सोहरे में लकड़ी के खिलौने तथा उज्जैन में बरिच फ्रिट में आगामी 5 वर्षों के लिए 37.50 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. तैयार की गयी है। इस परियोजना से स्थानीय शिक्षण, बुनकरों और कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, ब्रांडिंग, विपणन तथा बाजार उपलब्धता जैसी सुविधाओं प्रदान की जाएगी। यह परियोजना प्रदेश में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगिक विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मैहर, कैमोर और निमरानी में 3 नये औषधालयों को मंजूरी - मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआईसी) द्वारा मैहर (जिला-मैहर), कैमोर (जिला कटनी), तथा निमरानी (जिला खरगौन) में 3 नये औषधालयों को खोलने एवं चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि वितरण कंपनियों को अंशपूजी के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, यथा वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण और विकास कार्यों के लिए प्राप्त केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि राज्य की वितरण कंपनियों को राज्य शासन द्वारा अनुदान के स्थान पर अंशपूजी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। स्कीम के अंतर्गत माह नवम्बर 2024 तक ऋण के रूप में प्रदत्त राशि 887 करोड़ 91 लाख रुपये को राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूजी के रूप में प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।



स्पीकर बिरला के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव

गोर्गाई बोले-राहुल को बोलने नहीं दिया, रिजजू का जवाब-प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता

रिजजू ने कहा-

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोर्गाई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोक-टोका



गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता

पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन कितना सदन में दिखाई। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है।

गोर्गाई ने बिरला पर भेदभाव के 3 आरोप लगाए - 2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। स्पीकर स्पर ने उनके तर्क पर सबूत देने का कहा। 9 फरवरी को शशि थरुकर जब बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि बोलिए, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं जब माइक ऑफ किया गया हो।

● जब सेशन चलता है तो राहुल विदेश चले जाते हैं - संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजजू ने कहा - इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूँ 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं। किसी और की बात नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष पीएम को गले लगा रहा है।

प्रियंका ने कहा-

● राहुल की सच्चाई इनसे पचती ही नहीं है - प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं। वह नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होके इनके सामने सच बोल देते हैं। सच्चाई वो जो बोलते हैं वह इनसे पचती नहीं है। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने स्पीकर की गैर-मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर नियुक्त न करने पर सवाल उठाए। कहा कि चेयर पर बैठे जगदीशका पाल कैसे इस दौरान कार्यवाही चला सकते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोर्गाई ने कहा कि देश का नेतृत्व कमकोर और बुजुर्ग है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अनामदिक के थंबीदुर्ग को यह पद दिया गया था, जबकि, 17वीं और 18वीं लोकसभा में नहीं था।



संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट के लोग अभी बिल्कुल सुरक्षित नहीं

● अरुणाचल के बीजेपी एमपी तापिर

गाओ ने अपनी ही पार्टी पर बोला हमला

ईटानगर (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी एमपी तापिर गाओ ने दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नरसीय भेदभाव और हमलों की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उन्होंने सरकार से नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए एक

मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क पर विचार करने की अपील की। बीजेपी एमपी का यह बयान दिल्ली के साकेत इलाके में मणिपुर की एक महिला पर हाल ही में हुए हमले के बाद आया है। संसद के सामने बोलते हुए सांसद तापिर गाओ ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट के लोग अक्सर न सिर्फ नेशनल कैपिटल में बल्कि देश भर के मेट्रोपॉलिटन शहरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी एमपी ने कहा कि यह मामला पार्लियामेंट में जीरो आवर में उठाया जाएगा और एक डेली गैरेशन यूनिन होम मिनिस्टर से भी मिलेगा। तापिर गाओ ने आगे सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट जैसा कानून लाने पर विचार करना चाहिए।

साउथ दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं पर हमला - बता दें कि साउथ दिल्ली में रविवार को नॉर्थ-ईस्ट की दो महिलाओं पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक, यह घटना साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास एक पार्क के पास हुई, जहां मणिपुर की एक महिला और असम की उसकी दोस्त घूम रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उन पर कमेंट किया और जब एक महिला ने ऐतराज किया, तो बहस शुरू हो गई जो कथित तौर पर हिंसक हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एक टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित से संपर्क किया। आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं।

यूपी में अब नहीं हो पाएगी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री

● ओला-उबर पर भी सरकार का कंट्रोल

होगा, योगी कैबिनेट से 30 प्रस्ताव पास

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में योगी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान 31 प्रस्ताव पेश हुए। इनमें से 30 पारित हुए। सबसे बड़ा फैसला फर्जी रजिस्ट्री को रोकने को लेकर हुआ। स्टाप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया-यूपी में अब खतौनी और दस्तावेज की जांच के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। इससे कोई भी व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा। इससे न केवल आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि भू-माफियाओं के सिंडिकेट पर भी सीधी चोट होगी। वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया- कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे यूपी के 12,200 गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। योजना छात्रों, किसानों और मरीजों को शहरों तक आने-जाने में फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने



बताया कि ओला, उबर पर भी अब राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। उन्हें अब परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बिना मोडिकल, बिना पुलिस वेरिफिकेशन, बिना फिटनेस के कंपनी के वाहन नहीं चल सकेंगे। ओला, उबर के वाहनों की पूरी जानकारी ऐप में शामिल होगी। मंत्री ने बताया- गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट की जरूरत नहीं होगी। परिवहन टैक्स भी नहीं देना होगा। ऑपरेटर बस रोडवेज को अनुबंध पर भी दे सकेंगे। गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, आसपास के रूट के 15-20 गांवों, ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी। जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर वापस रात 8 बजे उसी गांव में पहुंचेगी।



भारत की 'ब्रह्मोस' खरीदेगा इंडोनेशिया

● 200 मिलियन से 350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी

फिलीपींस के बाद दूसरे देश ने दिखाई रुचि, सरकार भी खुश

इससे पहले फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल 2024 को सौंपी थी। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है।

भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर (3130 करोड़ रुपए) की डील की थी। इंडियन एयरफोर्स ने ए-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किमी है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति

सेकेंड होती है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है, जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को तटीय इलाकों (साउथ चाइना सी) में तैनात करेगा, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके।

ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में दो मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन, शिप, एयक्राफ्ट से दो ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकेंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती है। इसके अलावा भारत फिलीपींस को ऑपरेट करना सिखाएगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रिंको रिंकार्डो सिरैत ने सोमवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी। भारत और रूस की को-ऑनरशिप

वाली कंपनी ब्रह्मोस ने रॉयटर्स को बताया कि वह जकार्ता के साथ 200 मिलियन से 350 मिलियन की डील पर एडवांस्ड बातचीत कर रही है। रिंको ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडनाइजेशन का हिस्सा है।

भोपाल-इंदौर के दो रेस्टोरेंट ने दस करोड़ का टैक्स छिपाया

देशभर में एक दिन के सर्वे में आयकर विभाग ने पकड़ी है 408 करोड़ की टैक्स चोरी

भोपाल (नप्र)। आयकर विभाग ने देशभर में रेस्टोरेंट्स पर चलाए गए सर्वे अभियान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की कड़ी जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। इस दिन देशभर में रेस्टोरेंट्स पर एक साथ सर्वे अभियान चलाया गया था।

आगे बढ़ने के साथ और बढ़ सकता है। विभाग के अनुसार भोपाल और इंदौर के ढाबा में 8 मार्च को की गई जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। इस दिन देशभर में रेस्टोरेंट्स पर एक साथ सर्वे अभियान चलाया गया था।



देशभर में 408 करोड़ की बिक्री छिपाने का खुलासा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि देशभर में रेस्टोरेंट्स द्वारा बिक्री छिपाने के मामलों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। शुरुआती जांच में एक ही दिन के सर्वे में करीब 408 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट्स बिल डिलीट करने, रिंकार्डों में बदलाव करने और बिक्री कम दिखाने जैसे तरीके अपनकर टैक्स चोरी कर रहे थे।

सॉफ्टवेयर के जरिए बिक्री का डेटा किया जाता था डिलीट

जांच में सामने आया कि कई रेस्टोरेंट संचालक बिक्री छिपाने के लिए 'पेट पूजा' सॉफ्टवेयर समेत अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। भोपाल के स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में भी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा था। आरोप है कि रोजाना होने वाली बिक्री का डेटा सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया जाता था ताकि आय कम दिखाई जा सके। आयकर अधिकारियों ने जांच के दौरान इस डेटा को रीस्टोर कर लिया है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी शगुन भी सौंपा, नई दुल्हन को गिफ्ट में दिया एलईडी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अचानक हरियाणा के गोहाना पहुंचे। वह यहां गांव मदीना में एक किसान संजय की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। यह वही किसान हैं, जिनके खेत में साल 2023 में ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई की थी। सुबह करीब सवा 10 बजे राहुल यहां पहुंचे थे। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई लोगों ने उनका हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा-राहुल भाई राम-राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। राहुल करीब एक घंटे तक शादी वाले घर में रहे। इस दौरान दूध के साथ चूरा भी खाया।



कोई भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा

● मुख्य चुनाव आयुक्त बोले-स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता

कोलकाता (एजेंसी)। मुख्य चुनाव

आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। स्पेशल इंटरसिव रिवीजन का मकसद है कि सभी सही वोटर को वोट देने का अधिकार मिले और कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो। आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में हिंसा और डर के माहौल से मुक्त होकर मतदान कर सकें। कोलकाता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिन तक हुई बैठकों के बाद कहा कि आयोग ने राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह डर नहीं।



कुमार बोले-चुनाओ पर्व, पश्चिमबंगोर गर्वा

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां मतदान प्रतिशत हमेशा काफी अधिक रहता है। राज्य के मतदाता सविधान का सम्मान करते हैं और शांतिपूर्ण चुनाव में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग का एक नारा भी बताया- चुनावो पर्व, पश्चिमबंगोर गर्वा (यानी चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व है)। इसके पहले ज्ञानेश कुमार को सुबह फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञानेश कुमार दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे, जहां लोगों की भीड़ ने गो बैक नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। यह लगातार तीसरे दिन सीईसी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कालीघाट मंदिर में दर्शन करने और रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर भी एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने काले झंडे दिखाए थे।

नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षाबल के जवानों को मिली बड़ी जीत

● जहां हुआ था 'बीआर दादा' का एनकाउंटर वहां बना कैंप, ग्रामीणों में खुशी

नारायणपुर (एजेंसी)। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने नए कैंप की स्थापना की है। नए सुरक्षाकैंप की स्थापना से नक्सलवाद की गतिविधियों पर लगातार लगेगी वहीं, फोर्स की आवाजही भी आसान होगी। नए सुरक्षा कैंप की स्थापना से ग्रामीणों ने खुशी की लहर है। सुरक्षाबल के जवानों ने अबूझमाड़ में नक्सलवाद पर

अंतिम प्रहार शुरू कर दिया है। नारायणपुर के बोटेर में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप सफलतापूर्वक स्थापित किया है। बोटेर क्षेत्र को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यह वही इलाका है जहां सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के टॉप लीडर और संगठन के महासचिव बसवा राजू उर्फ नंबला केशव राव का एनकाउंटर किया था। बसवाराजू की बीआर दादा के नाम से भी जाना जाता था। बसवा राजू के एनकाउंटर

के बाद से यह इलाका नक्सलमुक्त माना जा रहा है। यहां कोई बड़ा नक्सली फिलहाल ऐक्टिव नहीं है। बोटेर इलाके में सुरक्षा कैंप की स्थापना से ओरछ से बीजापुर के भैरमगढ़ तक सीधी सड़क कनेक्टिविटी होगी। नारायणपुर में कैंप की स्थापना में नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइलर्स और सीआरपीएफ की 6 अलग-अलग वाहिनियों ने मुख्य भूमिका निभाई। सुरक्षाबल के अधिकारियों ने कहा

कि कैंप स्थापना से वेरकोटी, नीचेवारा और गुडेकोट जैसे अंदरूनी गांवों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा। इसके साथ ही लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इस कैंप की स्थापना से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। साल 2026 में यह नारायणपुर में सुरक्षाबल के जवानों द्वारा स्थापित किया गया यह छठवां सुरक्षा कैंप है। यह कैंप थाना ओरछ क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है और जिला मुख्यालय नारायणपुर से

लगभग 90 किलोमीटर है। रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां से कई अंदरूनी गांवों तक पहुंच आसान होती है। सुरक्षाबल के अधिकारियों ने कहा कि दशकों से अछूते रहे अबूझमाड़ के इस क्षेत्र में अब नक्सलियों की जगह विकास का शासन होगा, नारायणपुर पुलिस का दावा है कि अबूझमाड़ में माओवादी संगठन अब पूरी तरह से खत्म के कगार पर है।

यूपी चुनाव से ही लागू होगा 33 फीसदी महिला आरक्षण!

● कानून में संशोधन की तैयारी में सरकार, जल्द होगा निर्णय

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाले कानून में सरकार बदलाव करना चाहती है। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 में प्रावधान था कि जनगणना और परिशीलन के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब सरकार इसे 2027 के यूपी और उत्तराखंड चुनाव से ही लागू करने की तैयारी में है। पंजाब और गोवा के चुनाव भी यूपी के साथ ही होने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में विपक्ष की राय लेने का प्रयास किया है। उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से इस मसले पर बात की है। जानकारी के मुताबिक इन विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षण करने का फैसला लॉटरी सिस्टम से लिया जा सकता है।



यूएई में फंसे प्रदेश के लोगों को झटका शारजाह उड़ानें 22 मार्च तक स्थगित

इंदौर। अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अटक के प्रदेश के निवासियों, खासकर इंदौर और भोपाल के लोगों को गहरा झटका लगा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शारजाह से इंदौर आने वाली उड़ानों को 28 फरवरी से रद्द कर रखा था, जिसे अब 22 मार्च तक के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। कंपनी ने अपनी आधिकारिक साइट से भी इस सेवा को हटा लिया है, जिससे फंसे यात्रियों को अब दूसरे रास्तों से लौटना पड़ रहा है। पहले कंपनी ने शारजाह हवाई अड्डे के बंद होने का हवाला देकर उड़ानें रोक दी थीं। लेकिन, अब वहां से परिचालन सामान्य हो चुका है। इसके बावजूद सेवा बहाल नहीं

मुंबई, दिल्ली तक की उड़ानों के किराए एक लाख रुपए तक पहुंचे



की गई। कई यात्रियों ने 12 से 15 हजार रुपए में शारजाह-इंदौर टिकट बुक किए थे, लेकिन अब दुबई या अन्य जगहों से मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों तक पहुंचने वाली उड़ानों के दाम 80 हजार से एक लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। इसी तरह, दुबई-इंदौर सीधी उड़ानें भी एयर इंडिया और इंदौर गांधी

इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 20 मार्च तक स्थगित कर दी। जबकि, अबू धाबी से भोपाल की फ्लाइट्स स्पाइसजेट ने 25 मार्च तक रद्द की हैं। मुंबई-शारजाह रूट पर इंडिगो की कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।

23 मार्च से बुकिंग शुरू- कंपनी ने 22 मार्च तक की सभी उड़ानों को सिस्टम से निकाल दिया है और 23 मार्च से नई बुकिंग शुरू करने की बात कही है। हालांकि, युद्ध की अनिश्चितता के कारण यात्रियों का भरोसा डगमगा रहा है कि क्या यह सेवा वाकई चलेगी या फिर और विलंब होगा।

टिकट के दाम आसमान पर

इंदौर के व्यवसायी राहुल शर्मा ने बताया कि वह 5 मार्च की फ्लाइट के लिए 13,500 रुपए दिए थे। लेकिन, अब दुबई से मुंबई या दिल्ली होते हुए इंदौर पहुंचने के लिए कई गुना महंगे टिकट मिल रहे हैं। इस संकट में भोपाल की गृहिणी प्रीति पटेल भी फंसी हैं, जिन्होंने परिवार के साथ लौटने की योजना बनाई थी। अन्य प्रभावित उड़ानों में दुबई-इंदौर (एयर इंडिया, 20 मार्च तक रद्द), अबू धाबी-भोपाल (स्पाइसजेट, 25 मार्च तक स्थगित), मुंबई-शारजाह (इंडिगो, 50% उड़ानें प्रभावित) और शारजाह-मुंबई (फ्लाई दुबई, 18 मार्च तक सीमित) शामिल हैं। कुल 15 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इस युद्ध भय से रुकी पड़ी हैं।



पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर बंगाली चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्पभद्र भार्गव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में विश्वकर्म मधु वर्मा, महापौर परिषद के सदस्य, पापंदराण, भाजपा कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय सिंधिया के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इंदौर में दिन की गर्मी घटी, रातें हुई ठंडी, उत्तरी हवाओं से मौसम बदला

मौसम का मिजाज फिर उलट-पुलट, 8-10 दिन बाद पारा बढ़ेगा

इंदौर। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। रविवार को दिन का तापमान नीचे आया, जबकि रात का पारा चढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आ रही हवाओं ने इस बदलाव को जन्म दिया है। हालांकि, मामूली गिरावट के बावजूद दोपहर की तपिश में कोई खास राहत नहीं मिली। जल्द ही गर्मी फिर जोर पकड़ेगी। विमानतल मौसम केंद्र के आंकड़ों से पता चलता है कि रविवार का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से तीन डिग्री ऊपर था, लेकिन शनिवार से 0.6 डिग्री कम। रात का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य है, मगर शनिवार से 1.3 डिग्री अधिक। पिछले दिनों पश्चिमी हवाओं ने गर्मी बढ़ाई थी, लेकिन अब उत्तर की ठंडी हवाओं ने असर दिखाया। जल्द ही तापमान ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा।

8-10 दिन बाद गर्मी से राहत- विशेषज्ञों के अनुमान से कुछ दिन बाद तापमान तेजी से बढ़ेगा और कुछ दिनों में 38-



39 डिग्री तक पहुंच सकता है। सोमवार के बाद फिर गिरावट आएगी, जो 8 से 10 दिनों तक चलेगी। मार्च अंत में गर्मी अपने चरम पर होगी। मौसम विभाग के लंबी अवधि पूर्वानुमान में कहा गया है कि अप्रैल की शुरुआत में हीटिंग गर्मी पड़ेगी, जबकि मध्य मार्च में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की राहत मिल सकती है। लोगों को सलाह है कि दोपहर में बाहर कम निकलें और पानी का सेवन बढ़ाएं।

हवा और आसपास का हाल- मौसम केंद्र के अनुसार, रविवार को हवा की औसत तापमान तेजी से बढ़ेगा और कुछ दिनों में प्रति 12-15 किलोमीटर प्रति घंटा रही,

जिसमें उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा हावी थी। नमी का स्तर दिन में 25-30 प्रतिशत और रात में 50-55 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे सुबह की ठंडक महसूस हुई। इंदौर के अलावा देवास, धार और उज्जैन जैसे पड़ोसी जिलों में भी यही टेंडेंस दिखाई दे रही है, जहां अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री के दायरे में रहा। कोई वर्षा या कोहरा नहीं हुआ, लेकिन धुंध भरी सुबह हुई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एनयूआई) मध्यम स्तर पर रहा, जो धूल भरी हवाओं से प्रभावित था।

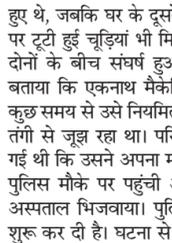
गर्मी फिर जोर पकड़ेगी

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आ रही हवाओं ने इस बदलाव को जन्म दिया है। हालांकि, मामूली गिरावट के बावजूद दोपहर की तपिश में कोई खास राहत नहीं मिली। जल्द ही गर्मी फिर जोर पकड़ेगी। पिछले दिनों पश्चिमी हवाओं ने गर्मी बढ़ाई थी, लेकिन अब उत्तर की ठंडी हवाओं ने असर दिखाया। सोमवार के बाद तापमान में फिर बदलाव दर्ज होगा।

आर्थिक तंगी से उजड़ा परिवार, पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली

दूध लेकर आए बच्चों के लौटते, सामने आया खतरनाक मंजर

इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। आर्थिक तंगी से परेशान एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गली नंबर 3 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान एकनाथ बाघ और उसकी पत्नी रोहिणी बाघ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 8 बजे एकनाथ ने अपने दोनों बच्चों को दूध लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। लगभग 20 मिनट बाद जब बच्चे वापस लौटे तो घर के भीतर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। पिता कमरे में फंदे पर लटक



हुए थे, जबकि घर के दूसरे हिस्से में मां का शव पड़ा हुआ था। मौके पर टूटी हुई चूड़ियां भी मिलीं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ होगा। थाना प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि एकनाथ मैकेनिक का काम करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे नियमित काम नहीं मिल रहा था और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपना मकान भी बेच दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

‘घर की सफाई कलेक्शन ड्राइव’ का शुभारंभ

इंदौर। नगर निगम इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और अभिनव पहल करते हुए ‘घर की सफाई कलेक्शन ड्राइव’ अभियान की शुरुआत की है। जोन क्रमांक 8 के वलासिक पूर्णमा कॉलोनी से महापौर पुष्पभद्र भार्गव और आयुक्त क्षिति सिंघल ने पांच विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। महापौर

पुष्पभद्र भार्गव ने कहा कि री-यूज का विचार भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। पहले घरों में बड़े भाई-बहनों की किताबें, कपड़े और अन्य सामग्री छोटे सदस्यों को दी जाती थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम ने यह अभियान शुरू किया है, जिसके तहत घरों में पड़ी अनुपयोगी लेकिन उपयोगी वस्तुओं को एकत्र कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिकों से कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने और अन्य उपयोगी सामग्री एकत्र कर केसराबाग ब्रिज के नीचे बने 3 क्रॉसरोड में छंटाई की जाएगी और ‘वेस्ट टू बेस्ट’ की अवधारणा के तहत उपयोगी वस्तुओं में बदला जाएगा।

दो युवकों की संदिग्ध हालत में मौत

इंदौर। शहर में शनिवार-रविवार को एरोड्रम और कनाडिया थाना क्षेत्र में दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक युवक दाबे से घर लौट रहा था तो दूसरा टूट खाली कर रहा था, तभी जान चली गई। एरोड्रम थाना क्षेत्र में फर्नीचर कारीगर दाबे से खाना खाकर पैदल घर लौट रहा था, तभी वह धुंके के बल गिरा। राहगीरों ने उसे अस्पताल भिजवाया, जहां कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ओंकार पिता मदनलाल (36) निवासी अशोक नगर के रूप में हुई है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिरने से युवक की नाक, आंख और माथे पर अंदरूनी और गंभीर चोटें आईं। कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित भूसांभडी बायपास पर टुक चालक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रायसेन जिले का रहने वाला चालक टुक में भूसा भरकर इंदौर आया था। वह भूसा खाली कर रहा था, तभी उसे सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

इंडिगो की दो फ्लाइट भोपाल डायवर्ट

इंदौर। सोमवार एयरपोर्ट के रनवे पर सोमवार को रिकॉर्पिंग का काम किया गया। रेगुलर निरीक्षण के दौरान रनवे के एक हिस्से में कुछ जगहों पर गीला बिटुमिन मिला, जिसके बाद सिविल इंजीनियरिंग टीम ने तुरंत एवशन लेते हुए 20 मिनट के अंदर जरूरी मरम्मत और सफाई काम को पूरा किया। इसके चलते दो यात्री विमानों को भोपाल की ओर डायवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक रनवे की रीकारपिंग का काम सोमवार को किया गया। इंदौर में तेज गर्मी है। रेगुलर निरीक्षण में पाया गया कि ज्यादा तापमान के कारण रनवे के एक हिस्से में डाली गई बिटुमिन की परत ढीली पड़ गई और निर्धारित मानों से ज्यादा ढीली हो गई थी। इसके बाद सिविल इंजीनियरों की टीम ने लगभग 20 मिनट के अंदर ही ये जरूरी काम पूरा कर दिया। इस काम के दौरान इंडिगो की दो फ्लाइटों (दिल्ली-इंदौर) और (रायपुर-इंदौर) को अस्थायी रूप से भोपाल डायवर्ट किया गया। वर्तमान में हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन सामान्य रूप से जारी है।

सांवेर में हनुमान मंदिर में मूर्ति से छेड़छाड़

इंदौर। सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचोला में स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में शनिवार देर रात मूर्ति से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव के ही दो युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना से गांव में नाराजगी और आक्रोश का माहौल है। पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचोला निवासी गजराज सिंह राजपुर शनिवार रात करीब 11 बजे अपने खेत की ट्यूबवेल बंद करने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंदिर के अंदर दीपक जलता देखा और वहां गांव के ही आकाश बागरी और अरुण बागरी को मौजूद पाया। गजराज सिंह को दोनों की गतिविधियां सदिग्ध लगीं, इसलिए वे मंदिर के अंदर पहुंचे और उनसे पूछताछ की, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। जब गजराज सिंह ने मंदिर में रखी हनुमान जी की प्रतिमा को देखा तो पाया कि मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। प्रतिमा पर लगा सिंदूर खुरच दिया गया था और उसमें गड्ढा कर उसे नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद गजराज सिंह ने तुरंत गांव के अन्य लोगों को मौके पर बुलाया।

रंग लगाने की बात पर विवाद भड़का

इंदौर। रंगपंचमी के जश्न के बीच मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। एरोड्रम थाना क्षेत्र के नगीन नगर में रंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि बहस बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते लात-घूंसे, पत्थर और चाकू तक चलने लगे। इस झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ितों सोहन तरेंडिया और सोनू के मुताबिक विवाद के दौरान आरोपी शुभम, उसकी पत्नी रितिका और साथी देवेंद्र विश्वकर्मा अचानक उग्र हो गए। आरोप है कि वे घर से हथियार लेकर आए और हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

तिलक नगर इलाके में लाखों की चोरी

इंदौर। पुलिस की रात्रि गश्त कमजोर होने का फायदा चोर उठाने में लगे हुए हैं। चोरों ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात तिलक नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाते हुए वहां से लाखों के जेवर और नकदी घर हाथ साफ कर दिया। घटना वृंदावन कॉलोनी स्क्रीम नंबर 140 में रहने वाली प्रीति पटेल के घर पर हुई। फरियादी ने बताया कि वे आवश्यक कार्य से कुछ दिन पहले घर से बाहर गई हुई थी। रविवार को जब घर लौटी तो चोरी का पता चला।

सिक्वोरिटी गार्ड ने आत्महत्या की कंपनी में ही फंदे पर शव मिला

मृतक के परिवार ने किसी तनाव की बात से इंकार किया

इंदौर। एक सिक्वोरिटी गार्ड ने सुसाइड कर लिया। लसूडिया में उसका शव सुबह दूसरे गार्ड ने फंदे पर लटकते देखा। परिवार ने किसी तरह के तनाव की बात से इंकार किया है। वहीं पुलिस ने कंपनी से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया था। आत्महत्या को इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। लसूडिया पुलिस के मुताबिक लोहा मंडी के पास एबीएस ऑटो कंपनी परिसर में सोमवार को गार्ड अरुण पुत्र नारायण गोरका निवासी भूमोरी का शव फंदे पर लटकते मिला। सुबह दूसरा गार्ड शिफट बदलने पर यहां पहुंचा तो अरुण को देखा। इसके बाद कंपनी के सुपरवाइजर और पुलिस को जानकारी दी। वेट शैलेन्द्र ने बताया कि पिता को किसी तरह का तनाव नहीं था। आत्महत्या के पीछे की वजह उन्हें नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ कंपनी से सामान गायब होने के चलते कंपनी के लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में अरुण को पूछताछ के लिए सोमवार को थाने आने के लिए कहा था। हालांकि अरुण के बेटे ने इस बात से इंकार किया है।

झड़प ने लगाई ब्रिज पर फांसी- भोपाल में रहने वाले एक झड़प का शव खुडैल के यहां पर नेमावर ब्रिज पर सुबह फंदे पर लटकते मिला। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम दीपक पुत्र विजय मालवीय निवासी निशातपुरा है। वह लोडिंग वाहन चलाने का काम करता है। उसने इंदौर से गुजरात के लिए माल भरा था। अलसुबह कुछ लोगों ने दीपक को ब्रिज के यहां फंदे पर देखा। तब नजदीक ही खड़ी गाड़ी की भी जानकारी ली। दीपक की गाड़ी में माल पूरा भरा हुआ था। उसके सुसाइड का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस परिवार को भोपाल में जानकारी दी है।

‘गेर’ में चैन स्त्रेचिंग करने वाली नेपाल बिहार की चादर गैंग के 20 गिरफ्तार

फ्लाइट से आकर करते थे वारदात, वापसी का भी टिकट बरामद



उत्सव में मोबाइल और चैन स्त्रेचिंग कर चुके हैं। एक साल पहले इंदौर आए थे। यहां की गैर में लाखों लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली थी। इसके चलते वे गैर मार्ग की रैकी कर चुके थे।

चार-चार की टोली - वारदात करने वाले युवक एक साथ होतलों, ढाबों और लॉजों से निकलते हैं। फिर एक स्थान पर इकट्ठे होकर वहां से चार-चार के ग्रुप में वारदात करने निकल जाते हैं। वारदात के बाद वे होटल, लॉजों में पहुंचते हैं। यहां लूट के माल का हिस्सा कर दूसरी दिन बिहार नेपाल लौट जाते हैं। युवकों के बारे में बिहार, नेपाल पुलिस से जानकारी निकाली तो पता चला कि उनके खिलाफ वहां भी केस दर्ज हैं। आरोपी कोई कामकाज नहीं करते। चोरी, लूट के माल को बेचकर आजीविका चलाते हैं। पुलिस

नालों में कचरा देखकर निगम कमिश्नर नाराज, सार्वजनिक शौचालय भी देखा

इंदौर में 2 सीएसआई, सहायक सीएसआई और दरोगा का वेतन काटा

इंदौर। नगर निगम के जोन 18, 8 और 5 के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे नाला आउटफॉल और नाला टैपिंग कामों को देखने के लिए सोमवार को नगर निगम कमिश्नर क्षिति सिंघल पहुंचे। निगम कमिश्नर जोन 8 में आने वाले तुलसी नगर इलाके में स्थित नाले को देखने पहुंचे। पहले वे जोन 18 में आने वाले कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के पीछे स्थित जगन्नाथ धर्मशाला के पास पहुंचे। यहां नाला आउटफॉल और नाला टैपिंग के कामों को देखा। यहां नाले के किनारे कचरा और गंदगी मिलने पर निगम कमिश्नर नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए, लापरवाही बरतने पर सीएसआई विनय मिश्रा, सहायक सीएसआई सोहन सिंह और इलाके के दरोगा अंजु रीत का तीन-तीन दिन का वेतन काटने को कहा। क्षेत्र में ही सार्वजनिक शौचालय को भी देखने पहुंचे। यहां सीटीपीटी की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली और मौके पर केयर टेकर भी नहीं था। इस पर उन्होंने संबंधित एजेंसी के खिलाफ आवश्यक



कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से कहा। उनके साथ अपर आयुक्त आशीष पाठक, सहायक यंत्री आकाश जैन, संबंधित जोनल अधिकारी, स्थास्थ्य अधिकारी, विभागीय अधिकारी भी थे।

एक दिन का वेतन काटा

इसके बाद निगम कमिश्नर जोन 8 में आने वाले तुलसी नगर इलाके में स्थित नाले को देखने पहुंचे। यहां नाले के किनारे किए

जा रहे आउटफॉल कामों को देखा और बचे हुए कामों को जल्दी पूरा करने के लिए बोला। यहां से वे जोन 5 में आने वाले मेघदूत नगर स्थित नाले में किए जा रहे आउटफॉल के काम को देखने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बचा हुए कामों को तय समय में पूरा करने को कहा। यहां नाले के आसपास गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और सीएसआई राम लोवंधी का एक दिन का वेतन काटने को कहा।

बाणगंगा में बदमाशों ने हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया

मारपीट, लूट के बाद चाकू-तलवार लेकर नाच रहे थे युवक

इंदौर। पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद शहर में बदमाशों के हासिल कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। मारपीट, लूट की घटनाओं के बाद अब वे खुलेआम हथियारों को प्रदर्शन कर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। बाणगंगा में रविवार को कुछ बदमाश चाकू तलवार लेकर नाचते नजर आए। बदमाशों का यह कृत्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस बदमाशों को धरपकड़ में जुट गई है। गोविंद नगर खारचा में रहने वाला अतुल ठाकुर और उसके दो साथी फिल्मी गाने पर नाच रहे हैं। इसमें अतुल और उसके दोनों साथियों के पास तलवार और चाकू थे। उन्होंने हथियारों को इस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया है।

बदमाशों के अकाउंट डिलीट

कुछ दिन पहले मूसाखेड़ी में रहने वाले दो बदमाशों ने जिला जेल के बाहर से वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। जेल अफसरों की शिकायत के बाद संयोजितागंज पुलिस ने दोनों से उठक-बैठक लगावाई थी। बाद में दोनों के अकाउंट से वीडियो भी डिलीट कराए गए थे। इसके पहले फ्राइम ब्रांच आकाश बकरी, भय्यू सुरीला और सलमान लाला जैसे बदमाशों के अकाउंट से इस तरह के वीडियो हटवा चुकी है। भाजपुको के नगर अध्यक्ष सोनात मिश्रा और युवा मोर्चा से जुड़े एक अन्य युवक के शादी कार्यक्रम में हथियारों के साथ वीडियो वायरल हुए थे। लेकिन हीरानगर और तैजाजी नगर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

संपादकीय

रावत की किस्मत पलटी

लगता है भाजपा नेता रामनिवास रावत की किस्मत ने फिर पलटा खया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के एक सदस्यीय बेंच ने विजयपुर सीट पर उपचुनाव में रावत को हारने वाले मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले पर अमल 15 दिन के लिए रोका ताकि मुकेश मल्होत्रा चाहें तो हाईकोर्ट की संविधान पीठ अथवा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि मुकेश मल्होत्रा को ऊंची अदालत से स्टे नहीं मिला तो रावत की विधायक के रूप में बहाली हो जाएगी। इस घटनाक्रम का मप्र की राजनीति पर भी असर होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले को जहां भाजपा ने न्याय की जीत बताया है, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को आदिवासी विधायक का हक छीना जाना निरूपित किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि मल्होत्रा ने जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह किया और आपराधिक केशों की अंधूरी जानकारी दी। इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्हा ने कहा कि मप्र के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी का चुनाव रद्द कर किसी को विजयी घोषित कर दिया गया हो। मुकेश मल्होत्रा के मामले में नामांकन पत्र की शुरुआत के तीन कॉलम में सारी जानकारी दी गई है, जबकि चौथे कॉलम में नहीं लिखा गया। केवल इस आधार पर किसी का चुनाव शून्य घोषित कर दिए जाने से सवाल उठता है कि क्या इतनी छोटी त्रुटियों पर विधायक का चुनाव शून्य घोषित हो सकता है? दरअसल मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी हैं, को कांग्रेस ने उपचुनाव में सामान्य सीट पर रामनिवास रावत के खिलाफ लड़ाया था, क्योंकि इस सीट पर आदिवासी वोटरों की संख्या काफी है। इस चुनाव में रावत मुकेश से हार गए थे। इसके पूर्व दो साल पहले ही रावत कांग्रेस की विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें वन मंत्री बना दिया था। चुनाव नतीजों के बाद पता चला कि मुकेश ने अपने शपथ पत्र में उन पर दर्ज अपराधों की पूरी जानकारी नहीं दी है। जबकि उन्हें 2014 के एक वन अपराध (क्रमांक 32773/2014) में सजा हुई थी। इसे पूरी तरह छिपाया गया। साथ ही अपने चुनावी हलफनामे में मल्होत्रा ने गलत घोषणा की थी कि उन पर लंबित आपराधिक मामलों (RCT No. 972/2022 व अपराध क्रमांक 93/2023) में आरोप तय नहीं हुए हैं, जबकि आरोप तय हो चुके थे। उन पर 3 लोगों के साथ मारपीट-गाली-गलौज के आरोप थे। वहीं, मुकेश मल्होत्रा ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ऐसे अखबारों में छुवाई जिनका प्रसार निर्वाचन वाले विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में नापना था। कोर्ट ने इसे वोटरों को अंधेरे में रखना माना। अदालत मुकेश के वकील ने पक्षकार के बचाव में कानूनी अज्ञानता की दलील दी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मल्होत्रा सामाजिक विज्ञान में एमए होने के साथ कानून के स्नातक (एलएलबी) भी हैं। ऐसे में दावा कि उन्हें आरोप तय होने के महत्व की जानकारी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि मल्होत्रा ने फॉर्म भरने वाले को गवाह के रूप में पेश नहीं किया और हलफनामे पर सत्यता की घोषणा बिना पढ़े हस्ताक्षर करने का दावा भी विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता को उम्मीदवार की आपराधिक पूछभूमि जानने का मौलिक अधिकार है ताकि वह सही निर्णय ले सके। हाई कोर्ट का यह फैसला दूरगामी और लोकतंत्र की पवित्रता के द्दित है। आगे क्या होता है, यह देखने की बात है।

ईरान में सत्ता संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और भारत की चिंता



नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह ईरान की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव है। ईरान की व्यवस्था हमेशा अपनी विचारधारा की निरंतरता और मजबूत संस्थाओं पर गंव करती रही है, लेकिन इतने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले नेता का अचानक चले जाना कई कमजोरियों को उजागर कर गया है। ईरान के सरकारी मौडिया ने 86 साल के सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि की है और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। लेकिन इस औपचारिक शोक से यह सच्चाई नहीं बदलती कि ईरान ने उस नेता को खो दिया है जिसने पिछले 37 वर्षों तक देश में धार्मिक सत्ता, सैन्य ताकत और राजनीतिक दिशा के बीच संतुलन बनाए रखा था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को ईरान की जनता के लिए न्याय बताया और खुलकर शासन परिवर्तन की बात कही। इससे यह घटना केवल नेतृत्व का संकट नहीं रह गई, बल्कि एक बड़े रणनीतिक मोड़ में बदल गई है। इसके जवाब में तेहरान ने इराक और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन घटनाओं से साफ है कि आने वाले समय में हालात शांत होने के बजाय और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं।

ईरान के संविधान के अनुसार, नए सर्वोच्च नेता के चयन तक एक अस्थायी तीन सदस्यीय परिषद सत्ता संभालती है। इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशन, न्यायपालिका प्रमुख गोलांम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल का एक न्यायविद शामिल होते हैं। कागजों पर भले ही यह व्यवस्था एक व्यवस्थित व्यवस्था का संकेत देती है, लेकिन वास्तविकता में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होगी। इन सबसे बीच में सबसे बड़ी उल्लेखनीय जो है वह है संभावित उत्तराधिकारियों की, उत्तराधिकारियों के रूप में कई नाम चर्चा में हैं। अयातुल्लाह अल्लौरजा अराफी, अयातुल्लाह मोहसिन अराफी, अयातुल्लाह हशेम हुसैनी बुशहरा और मोहसेनी-एजेई जैसे नाम धार्मिक व्यवस्था की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं कुछ अधिक विवादास्पद विकल्प भी सामने आए हैं, जैसे मौजतबा खामेनेई, जिन्हें सर्वोच्च नेता बनाए जाने पर वंशवादी उत्तराधिकार के आरोप लग सकते हैं, और इन

सबके इतर हसन खोमेनी का नाम भी चर्चा में है जिनका अपेक्षाकृत उदार रुख कट्टरपंथी धड़ों को असहज कर सकता है।

ईरान में वर्तमान परिस्थितियों में आगे की स्थिति तीन अलग-अलग दिशाओं में विकसित हो सकती है। पहला रास्ता नियंत्रित निरंतरता का है, जिसे खामेनेई के बिना भी खामेनेई की नीति कहा जा सकता है। इसमें कोई नया धार्मिक नेता औपचारिक रूप से सर्वोच्च पद संभालेगा, जबकि इस्लामिक रिवाल्यूशनरी गार्ड फॉर्स यानी आईआरजीसी वास्तविक शक्ति को और मजबूत करेगा। दूसरा विकल्प खुला सैन्य प्रभुत्व है, जिसमें आईआरजीसी सीधे तौर पर सत्ता पर हावी हो जाए और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका केवल प्रतीकात्मकता तक सीमित रह जाएं। तीसरा और सबसे अस्थिर विकल्प व्यवस्था के टूटने का है, जिसमें सत्ता के भीतर संघर्ष, जनता का असंतोष या सुरक्षा तंत्र में दरारें राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। हालांकि इन तीनों में से कोई भी रास्ता ईरान में सीधे लोकतांत्रिक परिवर्तन की गारंटी नहीं देता, क्योंकि आईआरजीसी अब भी व्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ है और विश्व बिखरा हुआ तथा अधिकांशतः विदेशों में मौजूद है।

सबसे महत्वपूर्ण है ईरान का पलटवार, खामेनेई की हत्या के बाद आक्रामक तरीके से ईरान को मिसाइलों ने इजराइल और कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद इजराइल ने देशभर में आपातकालीन सायन बजने लगे, भले ही अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया। इतना ही नहीं इराक, यमन और लेबनान में ईरान समर्थित संगठनों ने भी संघर्ष तेज करने की बात कही है। हालांकि आईआरजीसी के कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत के कारण कमाना और समन्वय की क्षमता पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

इन सब हालातों के बीच ईरान का तथ्यांकित एक्सिस ऑफ रीजेंट्स, जिसमें हिज्बुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल हैं, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद इन संगठनों ने केवल एक समर्थक ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक समन्वयक भी खो दिया है। इन सबसे बीच में डिस्ट्रुट हमले जारी रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले प्रॉक्सि युद्ध के लिए केंद्रीय नेतृत्व और वित्तीय समर्थन आवश्यक होता है, जो अब अनिश्चित हो गया है। इस बीच इजराइल इस स्थिति को ईरान के परमाणु ढांचे को और कमजोर करने के अवसर के रूप में देख सकता है। हालांकि यदि इस संक्रमण काल में ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इससे नए सैन्य हमलों की संभावना भी बढ़ सकती है।

अब अगर इन सारे वाक्यों को वैश्विक राजनीति और कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो खाड़ी के देशों के सामने अब

एक जटिल स्थिति पैदा हो गई है। वे भले ही निजी तौर पर ईरान की आक्रामक नीतियों पर लगाम लगाने का स्वागत करें, लेकिन साथ ही उन्हें मिसाइल हमलों, तेल आपूर्ति में बाधा, समुद्री मार्गों में असुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा खतरा भी झेलना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ताकालिक प्रभाव की जो आशंका है वह है ऊर्जा सुरक्षा की क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्गों में बढ़ते खतरे और हेमूजुज जलडमरूमध्य के संभावित बंद होने की आशंका ने तेल बाजारों को पहले ही अस्थिर कर दिया है। इतिहास गवाह है कि किसी शासन के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देना स्थिरता की गारंटी नहीं देता। 2003 में इराक और 2011 में लीबिया के उदाहरण आज भी चेतावनी की तरह हैं कि यदि ईरान में सैन्य प्रभुत्व बढ़ता है तो देश बाहरी स्तर पर अधिक आक्रामक और अंदरूनी स्तर पर अधिक दमनकारी हो सकता है। इसके इतर अगर हम देखें कि यदि धार्मिक नेतृत्व कायम रहता है तो वह व्यवस्था को बचाने के लिए सीमित स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है तो स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है, जैसे परमाणु सामग्री के बिखरने, जातीय विद्रोहों और एक कमजोर राज्य के उभरने की आशंका।

पूरी दुनिया की निगाहें इन घटनाक्रम पर बनी हुई हैं और आने वाले कुछ सप्ताह तीन महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेंगे। पहला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किस्तनी तेजी और एकजुटता से नया सर्वोच्च नेता चुनती है। दूसरा आईआरजीसी एकजुट रहता है या उसमें आंतरिक विभाजन उभरते हैं, और तीसरा क्या जनता का असंतोष सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बनता है। इस्लामी गणराज्य ने पहले भी कई संकटों का सामना किया है, लेकिन पहली बार वह अपने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता के बिना और बाहरी शक्तियों के सीधे सैन्य दबाव के बीच इस स्थिति से गुजर रहा है।

भारत के लिए यह घटनाक्रम पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया में नई अनिश्चितता लेकर आया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के कारण भारत हेमूजुज जलडमरूमध्य में किसी भी व्यवधान से सीधे प्रभावित होगा। यदि अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, सरकारी सॉक्सिडी पर दबाव पड़ेगा, रुपये की स्थिति कमजोर हो सकती है और आर्थिक संतुलन पर असर पड़ेगा।

ईरान में भारत की रणनीतिक परियोजना चाबहार बंदरगाह का भविष्य भी अनिश्चित दिखाई देता है। यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण मार्ग है और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारों का एक प्रमुख हिस्सा भी है। तेहरान में नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संभावित

सैन्य टकराव और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के कारण इस परियोजना की प्रगति धीमी पड़ सकती है। यह केवल एक व्यावसायिक परियोजना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को दरकिनार कर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में चिंता तो जताई है, लेकिन किसी पक्ष की खुली आलोचना से बचा है। इसकी वजह यह है कि भारत के संबंध एक साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ महत्वपूर्ण हैं। देश के भीतर ही इसका सामाजिक प्रभाव दिखाई दे सकता है। भारत के कुछ हिस्सों में शिया समुदाय ने शोक और नाराजगी व्यक्त की है, और यदि क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ता है तो स्थानीय स्तर पर तनाव की संभावना भी बढ़ सकती है।

आने वाले समय में भारत संभवतः सावधानी और संतुलन के साथ अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करेगा। भारत की कोशिश होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कुछ राहत मिले और नए ईरानी नेतृत्व के साथ संवाद और सहयोग की प्रक्रिया बनी रहे। साथ ही भारत यह भी चाहेगा कि उसकी महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना चाबहार बंदरगाह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहे, क्योंकि यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम रास्ता है। इसके साथ-साथ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगा। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस का आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए भारत अलग-अलग देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने और नए व्यापार तथा परिवहन मार्गों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठा सकता है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता न रहे।

हालांकि आगे की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान में नई सत्ता व्यवस्था किस रूप में उभरती है। अगर धार्मिक नेतृत्व पहले की तरह मजबूत बना रहता है तो नीतियों में निरंतरता देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सेना का प्रभाव बढ़ता है या सत्ता के भीतर संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने पक्षीय पड़ोस में तो या एक कड़ा धार्मिक शासन, एक मजबूत सैन्य राज्य या लंबे समय तक अस्थिर रहने वाले हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए आने वाले समय में संतुलित और सावधानीपूर्ण कूटनीति बेहद महत्वपूर्ण होगी।

खामेनेई की मौत केवल तेहरान में एक युग का अंत नहीं है। यह पूरे पश्चिम एशिया में गहरे रणनीतिक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत है। आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ इस अस्थिर दौर को किस तरह संभालती हैं, ताकि यह संकट किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए, जिसके परिणाम खाड़ी क्षेत्र से बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं।

दिल्ली शराब नीति : सारे दोषी डिस्चार्ज आप हुई रिचार्ज



विरलेषण

ऋतुपर्ण दवे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अखिलेश के नेतृत्व में, मनीष सिंसोदिया और बाकी अन्य 23 अभियुक्तों को शराब घोटाले के मामले में अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। जब अदालत को लगता है कि चार्जशीट में कई खामियाँ हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता और प्रथम जिय धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए, जो न हों तो अभियुक्तों को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जबकि अदालत सभी गवाहों के बयान और बचाव पक्ष के सारे सबूत देख कर, किसी अभियुक्त को निर्दोष करार देती है, तो बरी करना कहलता है। राजज एवेन्यू कोर्ट ने देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा रखे सबूतों को न केवल कमजोर बल्कि बेहद नाकामी माना। इस फैसले को लेकर पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। सीबीआई और ईडी के कामकाज के तौर तरीकों पर हमेशा से उंगली उठती रही। बड़ी जांच एजेंसियों की छवि पर भी बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं जो झलकता भी है। आम आदमी पार्टी पर दर्ज मामलों के पीछे राजनीतिक विन्धेय समझ आने लगा है। लोगों के जेहन में था, है और फिर कौंधा कि क्या जानबूझकर ऐसे मामले राजनीतिक पूर्वाग्रहवश दर्ज किए जाते हैं? पूरे मामले को देखने-समझने से ऐसा

प्रतीत होता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं था बल्कि प्रस्तुत आरोप पत्र (चार्ज शीट) में जबरदस्त खामियाँ और विरोधाभास भी था। अब मामला भले ही राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता का हो, देश की सबसे बड़ी और विश्वनीय समझे जाने वाली जांच एजेंसी को शामिल करने से कामकाज पर फिर उंगली उठ गई। ऐसा पहली बार भी नहीं है और न आखिरी बार होगा। दिल्ली की बहुवर्चिंत शराब नीति से जुड़े मामले में आए फैसले को बड़ा और अहम माना जा रहा है। इसने स्पष्ट किया कि महज दावों से काम नहीं चलेगा। आरोपों पर भरपूर के साथ में ठोस और पर्याप्त सबूत हों, जो नहीं थे। अदालत ने कई बार कहा कि जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत सबूत काफी कमजोर और अपर्याप्त हैं। बरी होने के क्रम में सबसे पहले कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे उन्हें, फिर मनीष सिंसोदिया और उनके बाद अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज किए गए।

चार्जशीट खामियों से भरी थीं जिससे सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसी पर दबाव था? जांच एजेंसी को पता था कि आरोपों में दम नहीं है और सबूत नाकामी है तो जल्दबाजी में बिना अध्ययन, चार्जशीट क्यों प्रस्तुत की गई। यह तो समझ आता है कि मामले के जांचकर्ताओं ने बेमन से केवल औपचारिकता निभाई। अदालत ने साफ कहा कि कई बिंदुओं का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी चलते सभी को राहत मिली।

दरअसल अदालतें सबूतों को प्रथम दृष्टया देख, तय करती हैं कि किन धाराओं

में मुकदमा चलना चाहिए। सीबीआई का आरोप था कि दिल्ली में 2021 में लाई गई नई शराब नीति एक साजिश थी जिसे चुनिंदा लोगों के लाभार्थ लाया गया। बाद में इसे हटा दिया गया। काफी वृद्ध फैसला जो कि 549 पन्ने का है में अदालत ने कई बार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए और कई निंदा की। मामले की शुरुआत चुनाव प्रचार से जुड़ी कपनियों से और छोटे व्यापारियों पर केन्द्रित थी जो बढ़ते-बढ़ते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं तक जा पहुँची। अदालत की यह टिप्पणी काफी मायने रखती है कि पूरा मामला महज कल्पनाओं यानी धारणाओं पर आधारित है न कि पुख्ता सबूतों पर। ऐसे में जांच टीम सवाल उठाना स्वाभाविक है।

यहां तक कि कोई भी सबूत यह नहीं दर्शाता कि मनीष सिंसोदिया कथित पैसों के लेन-देन में शामिल थे। अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ एक भी बरामदगी, दस्तावेज या पैसों के लेन-देन या ट्रान्सफर का कोई सबूत पेश कर पाई। बड़ी बात यह रही कि कथित घोटाले से जोड़ने खातिर इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप, दस्तावेज या लेन-देन का डिजिटल साक्ष्य भी नहीं है। अदालत ने पाया कि स्वतंत्र जांच करने पर भी पैसों की लेन-देन की कड़ी ऐसे दस्तावेजों पर आधारित है जो कतई कानूनन स्वीकार्य नहीं हैं। बयान भी ऐसे हैं जिसकी पुष्टि तक नहीं हुई। अदालत ने उन्हें मामूली कर्मियों न मान पूरे मामले की बुनियाद को ही शुरुआत से कमजोर माना। वहीं तथ्यों से अदालत संतुष्ट हुई कि शराब नीति एक सोची समझी थी जो सुयाजों से विमर्श कर, विधिवत लाई गई।

जबकि दिल्ली के उप राज्यपाल से विचार-विमर्श की कोई कानूनी या संवैधानिक जरूरत ही नहीं थी तब भी उनसे राय लेकर, नीति में जोड़ गया। पूरे मामले में केजरीवाल और सिंसोदिया और राजनीतिक दल के स्वयंसेवक भी शामिल थे। सीबीआई ने पाया कि जिन कुछ कारोबारियों को नई शराब नीति से फायदा हुआ वो 'साउथ ग्रुप' के थे। इस पर भी अदालत की आपत्ति आई कि नाम लोगों के क्षेत्र से जुड़ा है जिसका कानून से कोई मतलब नहीं। साउथ ग्रुप नाम प्रतिकूल प्रभाव के लिए उपयोग हुआ। अदालत ने यहां तक कहा कि कथित साजिश शुरुआत से ही लचर रही और लगने लगा कि सारा कुछ महज अटकलों का खेल है जो न कानूनन मान्य है और न ही सबूतों पर आधारित है। सरकारी गवाह बनाते वक्त भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। बार-बार नए आरोप जोड़ने से लगता है कि ऐसे लोगों को भी फंसाया गया जिनके विरुद्ध ठोस आधार ही नहीं था। केजरीवाल और सिंसोदिया समेत कई अभियुक्तों पर प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी, द्वारा एक 'मनी लॉडरिंग' केश भी चल रहा है। देखना है इस मामले में इस फैसले का कैसा असर पड़ता है?

यह तो तय है कि राजज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों होगा। बहरहाल बड़ी और प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को केन्द्रीय सत्ता की कठपुतली या तोता कहलाना अब भारत जैसे देश में अच्छे जरूर नहीं लगता! हां, आम आदमी पार्टी डिस्चार्ज होने से एक तरह से नया जीवनदान जो मिला।

जबकि दिल्ली के उप राज्यपाल से विचार-विमर्श की कोई कानूनी या संवैधानिक

सौंदला ग्राम : जाति तोड़ो, देश जोड़ो



अनुकरणीय

विकज जोशी

लेखक भेष भोपाल के पूर्व गुण महायंत्रक हैं।

दिलों में आग लगाएगा मैं दिलों की आग बुझाऊंगा उसे अपने काम से काम है मुझे अपने काम से काम है आजादी उपरांत के परिदृश्य में भारतीय राजनीति के पराभव में मुझे तथ्यांकित प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों का योगदान अधिक लगता है बनिस्वतन कम कम पढ़े लिखे आम भारतीयों के। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक कुन्दनी नेम ने आजादी बाद के पहले पांच दशक को भारतीय राजनीति के संदर्भ में अपनी एक पुस्तक को इन शब्दों में समर्पित किया है - 'समर्पित युद्धांग स्थित उस चाय की दुकान वाले को जिसका भारत की समस्याओं के संदर्भ में चिंतन दिल्ली में बैठे नेताओं के मुकाबले अधिक वास्तविक लगा। यह तो हुई पहली बात।'

दूसरी यह कि स्वाधीनता उपरांत राजनेताओं ने सामाजिक बुराइयों से निजात दिला पाने की कोशिशों के बजाय उसे बर्तज अंग्रेजी हुकमरानों की तर्ज पर 'डिवाइड एंड रूल' अर्थात् 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अखिरापर करते हुए अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए देश व समाज को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता जैसी बुराइयों के गहरे गड्डों में सदा के लिये डूबेले दिया।

इस संघर्ष में पिछले दिनों एक सुखद समाचार प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य से जब 5 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गाँव ने ग्राम सभा की बैठक में स्वयं को आधिकारिक रूप से 'जाति-मुक्त गाँव' घोषित किया। इस अवसर पर 'आमची जात-मानव' (मेरी जाति मानवता है) का नारा अपनया गया। सरपंच शरद अराड़े के नेतृत्व में इस पहल के तहत जाति-आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाया गया तथा सार्वजनिक

जीवन में समानता और एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। पहल के प्रमुख विवरण- उद्देश्य: दैनिक जीवन में जाति-आधारित पहचान और भेदभाव को समाप्त करना, जिसकी प्रेरणा डॉ. बी.आर. अंबेडकर और अन्य सामाजिक सुधारकों से ली गई है। प्रस्ताव का दायरा: यह प्रस्ताव सभी सामाजिक, सार्वजनिक और सरकारी गतिविधियों पर लागू होगा, जिससे मंदिरों, विद्यालयों और जलस्रोतों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कार्यान्वयन के उपाय: उद्घेन पर निगरानी रखने के लिए गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त सुझाव: गाँव ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और



भेदभावपूर्ण परंपराओं पर रोक। सामाजिक प्रभाव: यह स्वैच्छिक और सर्वसमत्त निर्णय सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और ग्रामीण भारत के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। न्याय के लिए कदम: यह कदम गहराई से जड़ जमा चुकी जातिगत विभाजनों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जन-आधारित पहल माना जा रहा है। नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं पर काश समाज समर्पित स्वयंसेवी समूह ही इस दिशा में सार्थक प्रयास करें तो अब भी बात बन सकती है अन्यथा हमारी सभ्यता और संस्कृति का विनाश अवश्यसंभावनी है ही।

पंछे मानव फूल जल अलग अलग आकार माटी का घर एक ही सारे रितरेदार मैं भी तू भी यात्री आती जाती रेल अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेला।

बैसाखीनंदन की बल्ले-बल्ले



व्यंग्य

सुरेश आध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

3 नके नामकरण संस्कार के पूर्व नाम निर्धारण को लेकर अपार शोध किया गया था. कुंडली में भी कुछ नाम सुझाए गए थे. मित्रों/रिशतेदारों से भी परामर्श किया गया था तथा विश्वगुरु 'गुरुल' की भी सहायता ली गई थी. सबसे सलाह मसवरे के बाद उनका नाम 'बैसाखीनंदन' तय किया गया था. संभवतः बैसाख माह में जन्म के चलते इस नाम पर सहमति बनी थी. नाम निर्धारण को लेकर जितनी साक्षरता होती है उसकी शतांश भी घरेलू नाम पर ही होती है. टीटू, पिंटू, चिंटू, बकटू, छूटकू आदि जो

भी अनायास जूबान पर आ जाए, वही नाम चल निकलता है. इस पर कोई बहस - विवाद नहीं होता है. जिस नाम के लिए मशकत होती है, उससे जुड़ा-टूटा, विकृत या अपभ्रंश प्रक्रिया में चलन में आ जाता है. यथा दिनेश्या, रमेश्या, जगदिश्या, सुरेश्या आदि. इन प्रचलन में आए नाम में जो लाड व अपनत्व झलकता है, वह मूल नाम में कन्हा? बैसाखीनंदन भी इसी तर्ज पर बैसाखी हो गया. विद्यालयीन शिक्षा तक तो उसे अपने नाम का अर्थ ही समझ में नहीं आया था. महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान एक सहपाठी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सकीय सलाह पर बैसाखी के उपयोग ने उनके ज्ञानचक्षु खोल दिए. नाम का अर्थ समझते ही उसे चरितार्थ करने में वे प्राण-प्रण से सहस्र संकल्प हठा ही उसकी भी जूरत थी. जन्हा किसी की जरूरत

होती वे बैसाखी बन जाते. परिस्थितिया बदलती तो उन्हें बैसाखी की जरूरत होती. मान-मनोवल करके वो किसी की भी अपनी बैसाखी बना लेते. इस प्रक्रिया में प्रयोग व अनुप्रयोग से वे सिद्धहस्त हो गए. बैसाखी बनना व बैसाखी बनाना उनके लिए बाए हाथ का काम हो गया. इस परिपक्वता से बैसाखीनंदन ने रफ्तार पकड़ ली और इसके सहारे फरफटें से दौड़ने लगे. सफलता उनके कदम चूमने लगी तो उपलब्धियों के नए आकाश वे छूने लगे. उनका नाम कामयाबी का पर्याय माने जाने लगा. इस बीच कुछ ज्योतिषियों/शुभचिंतकों/सलाहकारों ने उन्हें नाम बदलने की सलाह भी दी तथा जुगाडूला, पलटूराम जैसे नाम भी सुझाए. नाम बदलने की प्रक्रिया उठे झंझट महसूस हुई तथा इससे पहचान का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना भी

नजर आई, अतः इस विचार पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तथा बैसाखी पर ही टिके रहने का निश्चय किया. उम्र के एक पड़ाव पर उन्हें इस चारित्रिक गुण (विधा) के अपने साथ समाप्त/लुप्त होने का खतरा महसूस हुआ, अतः इसके संरक्षण व संवर्धन की जरूरत उन्हें महसूस हुई. सो एक योग्य व विश्वसनीय शिष्य की तलाश में बैसाखीनंदन जूट गए. हीरे की तलाश में जौहरी ने अपने आसपास से लेकर दूर दूर तक प्रदेश व देश के कोने कोने में तलाश की, अपने संसाधनों व जासूसों का भी उपयोग किया. उनकी पारखी नजर में कोई खरा उतरता नजर नहीं आया. उन्होंने अपनी दृष्टि पलटी, चित्त को आत्मकेंद्रित कर ध्यान की मुद्रा में घर में ही प्रतिभा की खोज में चिंतन मनन का विचार किया. ध्यान मुद्रा में कुछ समय गुजारने उपरांत आंख खोलते ही उनकी दिव्य दृष्टि अपने

सुयोग्य पुत्र पर गई. एक कुटिल मिश्रित मधुर मुस्कान उनके तेजस्वी मुख पर फैला गई. अपने आप से उन्होंने कहा 'मूरख, खाक में छोरों-ने गाम में ढिंढोरा.'

स्नान, ध्यान, पूजा-पाठ से निवृत्त होकर उन्होंने सहर्ष एक ओर 'बैसाखी' के अवतार की घोषणा कर दी. सहसा उन्हें याद आया 'एक और एक दो' के परे 'एक पर एक ग्यारह' होते हैं. ग्यारह बैसाखी के विचार से उनकी बल्ले बल्ले हो गई. उत्तराधिकारी की बल्ले बल्ले हो गई. सार्थक प्रयास करें तो अब भी बात बन सकती है अन्यथा हमारी सभ्यता और संस्कृति का विनाश अवश्यसंभावनी है ही।

स्वामी, सुबह सवेरे मौडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रियल पार्क, जांखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

मानवीय सवालों की सुनामी में बढ़ती समाधान शून्यता!

विचार

अनिल त्रिवेदी

लेखक अभिभाषक हैं।



हुआयामी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या सैनिक शासन सहित चाहे राजशाही भी क्यों न हो किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नित नये अनसुलझे या खड़े हो रहे सवालों के बोझ तले तेजी से सारी मनुष्य निर्मित व्यवस्थाएं एक तरह से ढहती जा रही है या समाधान शून्यता की दिशा में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यह पुरातन से लेकर आजतक के आधुनिक कालखंड का खुला सत्य है। जैसे सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है सत्य के साथ कोई विशेषण नहीं लगता। पर भारत जैसे दार्शनिक विरासत और परंपरा वाले अंतहीन विविधता और बहुलता वाले देश में भी सवालों की सुनामी तो दिन-प्रतिदिन गहराती ही जा रही है और साथ ही साथ समाधान शून्यता का ग्राफ भी दिन प्रतिदिन फैलता या बढ़ता ही जा रहा है। आज के कालखंड में बुनियादी सवालों के सहज समाधान क्यों नहीं मिल रहे हैं? पहले और आज में एक मौलिक अंतर तो यह हुआ है कि पुरानी या प्रागैतिहासिक दुनिया में सवाल कम थे और जीवन जीने के साधन भी बहुत कम थे फिर भी समाधान खोजने में और चुनौतियों से जुड़ते हुए जीवन जीने का रोमांच बहुत अधिक था। ऐसा इसलिए था कि मनुष्य मन में उठने वाले सवाल मनुष्य मन को चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी बताता था। आधुनिक सभ्यता में मौलिक अंतर यह उठ खड़ा हुआ है कि मनुष्य मन में जो सवाल उठ खड़े होते हैं उनका समाधान अकेले मनुष्य और शासन व्यवस्था दोनों के पास नहीं है। क्योंकि मनुष्य निर्मित साधनों का अंबार खड़ा हो गया है और प्राकृतिक रूप से जीवन में मिले तन और मन के साधनों की सनातन शक्ति को आज का मनुष्य और उसकी व्यवस्था अपनी स्मृति से विस्मृत कर चुकी है।

शुरुआती सभ्यता में अकेला मनुष्य अपने एकाकी प्रयास पर आधारित जीवन जीने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था पर आज की भीड़ भरी दुनिया में सब कुछ

वैश्विक हो रहा है अकेला मनुष्य अकेले अपना जीवन नहीं जी सकता। आज के मनुष्य के पास खुद के प्रयास से ज्यादा राज या शासन व्यवस्था के भरोसे या मदद के बिना जीवन जीने का कोई उपाय लगभग संभव नहीं रहा है। मनुष्य अपने जीवन काल में क्या खाये, क्या करें और कैसे जीवन व्यतीत करें? यह अकेले मनुष्य मन का खेल नहीं रहा है राज काज की कार्यप्रणाली की जकड़न में मनुष्य का जीवन उलझ गया है। अकेला मनुष्य सब कुछ कर सकता है पर अकेला चाकर भी सूकून के साथ जी नहीं सकता है। सरल जीवन विकास के नाम पर जटिल से जटिलतम होता ही जा रहा है। यदि वर्तमान काल की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है जिससे न तो अकेला मनुष्य और न ही समूची दुनिया कोई उपाय खोज पा रही है। आज के विकसित देशों और लगातार विकासशील देशों में जिस तरह से जीवन यापन कर सकना साधनों की प्रचुरता के बाद भी सरल सहज नहीं रह पा रहा है। आर्थिक संपन्नता मात्र से जीवन के मूलभूत सवालों को हल करने लायक आधुनिक काल का मनुष्य



रहा नहीं है। आधुनिक काल की संपन्न दुनिया में परिवहन के साधनों की संख्या जमीन और आकाश दोनों में दिन दूनी रात चौगुनी अराजक गति से बढ़ती ही जा रही है। इस कारण विकासशील देशों की पुरानी बसाहटें अनिर्वाह एवं अराजक यातायात व्यवस्था में या निरंतर वाहनों की भीड़ में बदलती जा रही हैं। एक और बड़ा

बदलाव दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रहा है कि सब इस अराजक स्थिति में चुपचाप जी रहे हैं और जीवन में आने वाले बुनियादी सवाल से नजरें चुरा रहे हैं। सवालों की चुनौती को अपने जीवन काल में समझ कर रास्ता निकालना ही मनुष्य जीवन की जीवनी शक्ति माना गया है। यदि मनुष्य समाज अपने वर्तमान काल की चुनौतियों का हल नहीं खोज पाए तो इसमें चुनौतियों की जटिलता न होकर मनुष्य जीवन की अकरमण्यता ही माना जाएगा। काल से नजरें चुरा कर आठ अरब जीवित मनुष्य तकनीकी अर्थ में जिनदा भले ही मानें जावें पर पर जिनदा होकर भी पूरी जिंदादिली एवं

पूर्णता से जी ही नहीं पा रहे हैं। समूची दुनिया में मनुष्य ही अकेला जीव या प्राणी है जिसने समूची दुनिया में अपनी बुद्धि और कृतित्व से अंतहीन परिवर्तन किए हैं। मानव समाज को चलाने वाले बुनियादी ढांचे को खड़ा कर व्यवस्था बनाई है पर मनुष्य द्वारा सोची और निर्मित व्यवस्था आज जैसे काम

नहीं कर पा रही है जैसा मनुष्य ने आदिकाल से आज तक सोचा था। यही प्राकृतिक दुनिया और मनुष्यकृत दुनिया का भेद है। मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवस्था या विचार या स्वरूप हमेशा या मनुष्य द्वारा निर्मित नियम या व्यवस्था अनुसार नहीं हो सकता पर प्राकृतिक व्यवस्था सदैव या अपने सनातन स्वरूप में यथावत स्वरूप में गतिमान बनी हुई है। मनुष्य प्रकृति का अंश है प्रकृति का नियंत्रण नहीं। इसी से मनुष्य के मन में जो व्यवस्था खड़ी होती है उसके अनुसार मनुष्य का कृतित्व तो निर्धारित होता रहता है। पर प्रकृति के स्वरूप पर उसका कोई सर्वकालिक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति में न तो सवाल उठते हैं और न ही समाधान खोजने की कोई व्यवस्था है। सब कुछ अपने आप होता ही रहता है। प्रकृति का अपना प्राकृतिक चक्र है जो निरंतर जारी है। उसमें मनुष्य व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता युद्ध भी मनुष्य के मन की उपज है जबसे दुनिया बनी असंख्य युद्ध छोटे बड़े स्वरूप में हो चुके हैं पर लड़ने वाले लोग थक कर युद्ध बंद कर देते हैं या युद्ध को हल मानने वाले थक कर युद्ध बंद कर देते हैं। युद्ध प्राकृतिक स्थिति नहीं है। युद्ध तो मनुष्य मन की असफलताओं का नंगा नाच है। इस तरह हम मान सकते हैं प्रकृति में न कोई सवाल है न ही समाधान खोजने का कोई उपाय। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण में कोई अपूर्णता नहीं कोई सवाल नहीं कोई समाधान नहीं। जैसे सत्य हमेशा से सत्य ही है इसमें कोई घट-बढ़ नहीं है। मनुष्य प्रकृति का अंश है और अंश प्रकृति से एकाकार ही ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रकृति का अपना चक्र नहीं बदल सकता।

प्रकृति

प्रो. अरिस्मता सिंह

लेखक संभकार हैं।



पर्यावरण संकट के समकालीन दौर में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो गया है कि क्या केवल तकनीकी उपायों और नीतिगत घोषणाओं से धरती को बचाया जा सकता है, या इसके लिए समाज की संरचना और सोच में भी परिवर्तन आवश्यक है। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि प्रकृति की रक्षा और समाज में महिलाओं की गरिमायुगी भागीदारी एक-दूसरे से अंतर्संबंध प्रक्रियाएँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन, जल संकट, जैव विविधता का क्षरण और प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ वैज्ञानिक या तकनीकी समस्या से इतर सामाजिक संरचना, संसाधनों के वितरण और नेतृत्वकारी भूमिका की दिशा से भी प्रभावित हैं।

इसी वैचारिक धरातल पर 'इको फेमिनिज्म' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो उठती है। इको फेमिनिज्म यह प्रतिपादित करता है कि प्रकृति और स्त्री दोनों के साथ होने वाला शोषण एक ही प्रभुत्ववादी मानसिकता का परिणाम है, और इसलिए दोनों की मुक्ति परस्पर संबद्ध है। यह सोच कागज़ी चर्चा भर नहीं है; यह विकास की उस वैकल्पिक दृष्टि को सामने लाता है जिसमें संवेदनशीलता, संरक्षण और सहभागिता को केंद्र में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण में नारी सशक्तीकरण पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। हम देखते हैं कि ग्रामीण और हार्शिये पर खड़े समुदायों में महिलाओं का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। वे जल लाती हैं, ईंधन एकत्र करती हैं, खेतों में मेहनत करती हैं और परिवार के पोषण

पर्यावरण रक्षा और नारी सशक्तिकरण

इसी वैचारिक धरातल पर 'इको फेमिनिज्म' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो उठती है। इको फेमिनिज्म यह प्रतिपादित करता है कि प्रकृति और स्त्री दोनों के साथ होने वाला शोषण एक ही प्रभुत्ववादी मानसिकता का परिणाम है, और इसलिए दोनों की मुक्ति परस्पर संबद्ध है। यह सोच कागज़ी चर्चा भर नहीं है; यह विकास की उस वैकल्पिक दृष्टि को सामने लाता है जिसमें संवेदनशीलता, संरक्षण और सहभागिता को केंद्र में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण में नारी सशक्तीकरण पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है।

की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसीलिए जब नदियाँ सूखती हैं, जंगल कटते हैं या भूमि की उर्वरता घटती है, तो उसका पहला प्रभाव महिलाओं की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनेक सामाजिक मंचों पर प्रकाशित विश्लेषणों में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि महिलाएँ केवल संकट की शिकार नहीं हैं, बल्कि समाधान की सक्रिय और सशक्त वाहक भी हैं और पर्यावरण को बचाने में नरिवाद एक बेहतर माध्यम की तरह काम करता है।

वैश्विक स्तर पर UN Women की रिपोर्ट भी यह रेखांकित करती है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन, खाद्य असुरक्षा और गरीबी की स्थितियाँ विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को अधिक प्रभावित कर सकती हैं। यह रिपोर्ट 'नारीवादी जलवायु न्याय' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताती है कि समाधान केवल तकनीकी

नवाचारों या कार्बन उत्सर्जन में कटौती तक सीमित नहीं हो सकता; इसके लिए ऐतिहासिक असमानताओं की पहचान, संसाधनों का न्यायपूर्ण



पुनर्वितरण, महिलाओं के नेतृत्व को मान्यता और नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अर्थात् जलवायु संकट का समाधान तभी प्रभावी होगा जब वह सत्ता-संबंधों और लैंगिक संरचनाओं में परिवर्तन को भी साथ लेकर चले।

दरअसल नारी सशक्तीकरण का आशय केवल शिक्षा या रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है; यह आत्मनिर्णय, स्वामित्व और नेतृत्व की क्षमता को सुदृढ़ करना है। यदि महिलाओं को भूमि पर अधिकार, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो वे टिकाऊ कृषि, जल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही यह भी एक कठोर सत्य है कि अनेक संस्थानों चाहे वे प्रशासनिक हों या नीति-निर्माण से जुड़े में आज भी महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व की स्वीकृति पाने के लिए अदृश्य अवरोधों और पक्षपात का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवरोध न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को सीमित करते हैं, बल्कि पर्यावरणीय निर्णयों में विविध अनुभवों और दृष्टियों की कमी भी उत्पन्न करते हैं। दुखद है कि वैश्विक युद्ध की स्थितियों में महिलाएँ युद्ध

की पीड़ा को सबसे निकट से झेलने वाले वर्गों में शामिल होती हैं; वे विस्थापन, प्रियजन को खोना, आजीविका की हानि, खाद्य असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे बहुआयामी संकटों का भारी बोझ सहती हैं। अनेक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में वे शरणार्थी बनकर असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन यापन करने को विवश होती हैं, जहाँ सामाजिक असुरक्षा, लैंगिक हिंसा और मानसिक आघात की चुनौतियाँ उनके सामने उपस्थित रहती हैं। फिर भी आपदा और संघर्ष की घड़ी में वही महिलाएँ समुदायों को संगठित रखने, सीमित संसाधनों में जीवन को पुनर्स्थापित करने और शांति-स्थापना की प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान देने का कार्य करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि शांति-वार्ताओं और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में उनकी सार्थक भागीदारी से स्थायी शांति की संभावना बढ़ती है, किंतु औपचारिक सुरक्षा और शांति-प्रक्रियाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी अपेक्षाकृत सीमित बनी हुई है। प्रकृति और नारी दोनों की गरिमा और सुरक्षा एक-दूसरे से संबद्ध है। यदि हम धरती को सुरक्षित और संतुलित रखना चाहते हैं, तो हमें समाज में नारी अस्मिता को भी समान महत्व देना होगा। महिलाओं की भूमिका और अनुभवों को महत्व दिया जाना सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन की अनिवार्य शर्त है तभी भविष्य अधिक सुरक्षित और मानवीय बन सकेगा।

स्मृति शेष

कुमार सिद्धांत

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

मध्य प्रदेश में शिक्षक शिक्षा और शिक्षा-चिंतन के क्षेत्र में सक्रिय रहे 90 वर्षीय सुरेंद्रनाथ दुबे ऐसे ही व्यक्तित्व थे, जिन्होंने लगभग पाँच दशकों तक शिक्षा जगत में मौन किन्तु प्रभावशाली भूमिका निभाई। 8 मार्च को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनका जीवन शिक्षक शिक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षक कल्याण और मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए निरंतर संघर्ष और साधना का जीवन रहा।

सुरेंद्रनाथ दुबे उन शिक्षाविदों में थे, जिनकी पहचान पदों या उपाधियों से नहीं, बल्कि उनके काम और विचारों से बनी। वे शिक्षक शिक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षक कल्याण और शैक्षिक विमर्श के ऐसे कर्मठ साधक थे जिनकी दृष्टि शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा तक सीमित नहीं मानती थी। उनके लिए शिक्षा समाज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया थी। सुरेंद्रनाथ दुबे का जीवन प्रारंभ से ही शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ा रहा। उन्होंने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न स्तरों को करीब से देखा और समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके विचारों और कार्यों का आधार बना।

वे मध्यप्रदेश प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे और शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT),

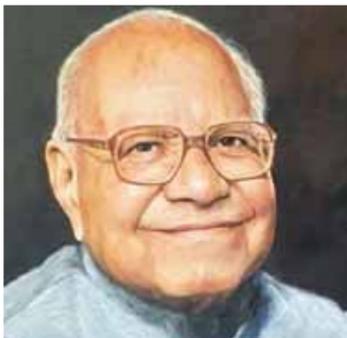
शिक्षक, विचार और समाज के प्रति समर्पित जीवन

भोपाल में कार्य करते हुए उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास और शैक्षिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। दुबे जी का मानना था कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का आधार शिक्षक होता है। यदि शिक्षक सक्षम, संवेदनशील और प्रशिक्षित होंगे तो शिक्षा अपने आप प्रभावी हो जाएगी।

इसी दृष्टि से उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षकों को विचार और संवाद का मंच प्रदान किया। वे परिषद की प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिका 'पलाश' से भी जुड़े रहे और इसके माध्यम से शिक्षा, शिक्षाशास्त्र और समाज से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाया।

सुरेंद्रनाथ दुबे का योगदान केवल संस्थागत या प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। वे शिक्षा से जुड़े व्यापक नीतिगत प्रश्नों पर भी सक्रिय रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। दुबे जी इस विचार के प्रबल समर्थक थे और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए लगातार आवाज उठाते रहे।

1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इस परिवर्तन के पीछे जो बौद्धिक और वैचारिक वातावरण बना, उसमें दुबे जी जैसे शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के पक्षधर थे और इस विषय पर लेखन तथा संवाद करते रहे।



बाद में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में पहल हुई और 86वें संविधान संशोधन (2002) के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, तब भी दुबे जी ने इस विषय पर अनेक लेख और सुझाव दिए।

दुबे जी का एक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक समुदाय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। वे मानते थे कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सीधे-सीधे शिक्षक की स्थिति और सम्मान से जुड़ी होती है।

इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए कई पहलें कीं। मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में 'शिक्षक सदनों' की स्थापना में उनका

योगदान उल्लेखनीय रहा। इन शिक्षक सदनों का उद्देश्य शिक्षकों को संवाद, प्रशिक्षण और सामूहिक गतिविधियों के लिए एक सड़ा मंच प्रदान करना था। शिक्षक समुदाय को संगठित और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों और बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाई। सुरेंद्रनाथ दुबे का दृष्टिकोण केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय विमर्श से भी जुड़े रहे। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और वैश्विक शिक्षा परिदृश्य को समझने का प्रयास किया। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. गुलाब चौरसिया के साथ उनके संवाद और सहभागिता ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया।

युनेस्को से जुड़े कार्यक्रमों और चर्चाओं में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। शिक्षा को मानवता, शांति और वैश्विक सहयोग से जोड़ने का विचार उनके चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुरेंद्रनाथ दुबे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी गांधीवादी विचारधारा थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ. एस. एन. सुब्बाराय दुबे के संपर्क में रहे और उनसे प्रभावित भी हुए। गांधीवादी सोच के कारण उनके विचारों में अहिंसा, नैतिकता, सामाजिक समानता और सेवा की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती थीं।

दुबे जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत स्पष्ट और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मनुष्य को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना है। वे अक्सर कहते थे कि यदि शिक्षा

में मानवता, करुणा और अहिंसा के मूल्य नहीं होंगे, तो वह अधूरी शिक्षा होगी। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में शांति और सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत कर सकती है। उन्होंने कई लेखों और व्याख्यानो में यह विचार व्यक्त किया कि शिक्षा को मानवता की सेवा के साथ जोड़ना आवश्यक है।

सुरेंद्रनाथ दुबे का व्यक्तित्व जितना विद्वत्तापूर्ण था, उतना ही सरल और विनम्र भी था। वे अपने काम को ही अपनी पहचान मानते थे और व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहते थे।

सुरेंद्रनाथ दुबे लंबे समय तक शिक्षक समुदाय के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। वे अनेक शैक्षिक मंचों और समूहों से जुड़े रहे और शिक्षकों को आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल नीतियों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की प्रतिबद्धता और समाज के सहयोग से संभव है।

सुरेंद्रनाथ दुबे का जीवन शिक्षा, सादगी और सेवा का का अद्भुत संगम था। सुरेंद्रनाथ दुबे का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र था। वे अपने कार्यों का प्रचार-प्रसार करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने जिस निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका योगदान यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल संस्थानों और नीतियों का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की चेतना और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तहत अंडर-13 टीम के खिलाड़ियों का चयन ट्रायलस

धार। संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर के निर्देश पर धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर-13 के लेटर बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन 15 मार्च रविवारको प्रातः 10 बजे डी.आर.पी.लाईन न्यू क्रिकेट मैदान पर होगा जिले की समस्त तहसील के खिलाड़ी चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं भाग लेने हेतु कट आफ डेट 1 सितंबर 2012 से 1 अगस्त 2015 के मध्य जन्म लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रखी गई है। प्रतिभागी खिलाड़ियों को पंजीयन कराना आवश्यक होगा एवं स्वयं की क्रीडा साथ में लाना होगी पिछले 3 वर्षों की ओरिजनल अंकसूची, आधार कार्ड एवं डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क 300 रुपए रहेगा। अंडर-13 का टूर्नामेंट खरागोन में 20 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर चयन स्पर्धा में भाग लें। यह जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता कुशल शर्मा ने दी।

संपत्ति-कर, जल-कर और मलबा शुल्क में वृद्धि से आम-जनता पर बढ़ेगा बोझ : गौतम देवास।

गौतम देवास। गत दिनों आयोजित नगर निगम एमआईसी की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार संपत्ति कर, जलकर और मलबा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास किया गया है। शहर कोरिस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने एमआईसी के इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। शहर कोरिस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने कहा है कि एमआईसी की आम जनता पहले ही महंगाई, जगह-जगह गंदगी और अतिक्रमण से परेशान हैं, तो दूसरी ओर शहर का व्यापारी वर्ग, अख्यस्थित मार्ग चौकीकरण से त्रस्त है व दूकाने और व्यापार ठप हैं, इन सबके बावजूद नगर निगम प्रशासन का करों में वृद्धि का प्रस्ताव, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। देवास की जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर, उन्हें देवास के विकास की लगाम दी थी, अफसोस है कि वे ही जनविरोधी नीतियों को लागू करने पर उतारू हैं। श्री गौतम ने महापौर और एमआईसी से जनहित में, प्रस्तावित कर वृद्धियों को वापस लेने की मांग की है।

पीएफ अंशदान जमा नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

देवास। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देवास के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कंपनी पर पीएफ अंशदान जमा नहीं करने और पेंशन प्रारंभ नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर से आवेदन देकर शिकायत की है। एमजी रोड निवासी जयंतिलाल जैन (62 वर्ष) ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि वे कंपनी में कर्मचारी रहित कर्मचारी क्रमांक 8592 के अंतर्गत वर्ष 1984 से अगस्त 2023 तक लगभग 39 वर्षों तक कार्यरत रहे। 1 सितंबर 2023 को कंपनी ने उन्हें सेवानिवृत्ति पत्र प्रदान किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब 18 माह बीत जाने के बाद भी उनके पीएफ खाते में पूर्ण अंशदान जमा नहीं किया गया और न ही पेंशन प्रक्रिया शुरू की गई। जैन ने बताया कि यह एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविशंस एक्ट, 1952 सहित श्रम कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में कई बार कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारी पंकज जैन से संपर्क किया गया तथा प्लॉट हेड रविंद्र गोयल और एचआर हेड सुरेंद्र से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जयंतिलाल जैन ने बताया कि अगस्त 2024 में उनकी बायपास सर्जरी हुई थी, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इलाज के लिए अंतर लेना पड़ा। वर्तमान में भी उन्हें हर महीने दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा है। उनके परिवार में दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा मानसिक रूप से दिव्यांग है और परिवार में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कंपनी को उनके पीएफ की पूरी राशि जमा कराए और पेंशन शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ श्रम कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

करंट से युवक की मौत, बोर्ड में प्लग लगाते समय हादसा

बैतूल। आठनेर क्षेत्र में करंट लगने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजन उसे गंधीर हलत में जिला चिकित्सालय बैतूल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ग्राम छिन्वाड़ा, पोस्ट हंडौनी, थाना आठनेर निवासी शिव शंकर पिता पंजाबराव इवने (24) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11 बजे वह अपने घर में बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था या स्विच चालू कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। करंट लगने के बाद परिजन उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज संभव नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद तड़के करीब 3 बजे डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया।

जल संसाधन विभाग ने तैयार की डीपीआर, नपा के पास सिर्फ 4 करोड़

7 करोड़ में बने बैराज की 18 करोड़ से होगी मरम्मत



एस. द्विवेदी, बैतूल। खेड़ी स्थित ताप्ती नदी पर बने ताप्ती बैराज की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग ने डीपीआर तैयार कर ली है। बताया गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में करीब 18 करोड़ रुपये से अधिक खर्च का अनुमान लगाया गया है, जबकि नगरपालिका ने अमृत योजना के तहत बैराज की मरम्मत के लिए करीब 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऐसे में लागत को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। दरअसल ताप्ती बैराज का निर्माण वर्ष 2018 में किया गया था। अमृत योजना के अंतर्गत 6.92 करोड़ रुपये की लागत से बने बैराज का उद्देश्य नदी में जल स्तर बनाए रखना और आसपास के क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। लेकिन निर्माण के महज एक वर्ष बाद ही ताप्ती नदी में बाढ़ के दौरान बैराज की की-वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से प्रभावित हिस्से की स्थायी मरम्मत नहीं हो सकी है और समय-समय पर अस्थायी उपायों से ही इस स्थिति संभालने का प्रयास किया जाता रहा है। अब जल संसाधन विभाग बैतूल ने जो

डीपीआर तैयार की है, उसके अनुसार इसमें करीब 18 करोड़ से अधिक की लागत आ रही है, जबकि नगरपालिका की समस्या यह है कि उसके पास इस कार्य हेतु मात्र 4 करोड़ रुपये का फंड है। ऐसे में शेष राशि जुटाना नपा के लिए बड़ी चुनौती होगी।

बैराज की मरम्मत के लिए कराई थी सॉल्व टेरिस्टिंग – जल संसाधन विभाग ने बैराज की मरम्मत को लेकर सॉल्व टेरिस्टिंग कराई थी। जांच में सामने आया कि जिस स्थान पर की-वॉल क्षतिग्रस्त हुई है वहां लगभग चार मीटर तक मिट्टी और रेत की परत मौजूद है और ठोस चट्टान का आधार नहीं है। इस कारण स्थायी मरम्मत के लिए मजबूत संरचना तैयार करने की जरूरत बताई गई है। डीपीआर के अनुसार बैराज की सुरक्षा के लिए 55 मीटर लंबा वीवर और बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही डाउन स्ट्रीम में 30 मीटर की वक्रेट का निर्माण किया जायेगा। कुल 55 मीटर लंबा कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्रस्तावित की-वॉल की चौड़ाई लगभग 2 मीटर और लंबाई 30 मीटर की होगी। इन सभी कार्यों को मिलाकर मरम्मत की अनुमानित लागत लगभग 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है।

वास्तविक लागत और उपलब्ध बजट के बीच बड़ा अंतर

ताप्ती बैराज की मरम्मत कार्य की वास्तविक लागत और उपलब्ध बजट के बीच बड़ा अंतर होने के कारण बैराज की स्थायी मरम्मत फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। जल संसाधन विभाग ने बैराज के क्षतिग्रस्त हिस्से की तकनीकी जांच के बाद डीपीआर तैयार की है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार डीपीआर को जांच के लिए अधीक्षण अधीक्षण यंत्रों कार्यालय भेजा गया है। परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह डीपीआर नगरपालिका को सौंप दी जाएगी। इसके बाद यदि आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाती है तो टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मरम्मत कार्य शुरू किया जा सकेगा। यदि नपा फंड की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो जल संसाधन विभाग खुद प्रस्ताव आला अफसरों को भिजवायेगा। इधर नपा की समस्या यह है कि उसके पास इस कार्य के लिए मात्र 4 करोड़ रुपये का ही फंड है।

देवास कलेक्टर ने स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दिये दिशा-निर्देश/पालकों को मिलेगी राहत

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुजा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) (2) के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के लिए निर्देश जारी किये हैं।

जारी निर्देशानुसार स्कूल संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे एवं विद्यालयीय सार्वजनिक सूचना पटल/स्थान पर चप्सा करेंगे। मान्यता नियमों के अन्तर्गत स्कूल की स्वयं की वेबसाइट होना अनिवार्य है। स्कूल के प्राचार्य/संचालक पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के साथ ही नवीन सत्र प्रवेश होने के एक माह पूर्व पुस्तकों की सूची विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

स्कूल संचालक/प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 30 अप्रैल 2026 तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल

माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र का उपयोग यथासंभव विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन व्यवहारिक ज्ञान एवं रीवीजन के लिए किया जाए।

स्कूल जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बी.एस.ई./माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि से सम्बन्ध है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिकरूप से अधिकृत एजेंसी यथा एन.सी.ई.आर.टी. म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए न्यूनतम रखे ताकि अभिभावकों पर वित्तीय भार कम हो।

सी.बी.एस.ई बोर्ड से सम्बन्ध समस्त विद्यालयों में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ही क्रय की जायेंगी। म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 2 मार्च 2020 द्वारा सभी अशासकीय, हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा मुद्रित पुस्तकों के द्वारा ही विद्यालय में शिक्षण का कार्य कराया जाएगा। विद्यालय आवश्यकतानुसार नियत पाठ्यक्रम अंतर्गत अन्य सहायक पुस्तकें नियत संख्या में उपयोग में ला सकेंगे जैसा

कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल के बस्ते का वजन कक्षा 1 से 2 के लिए 1.5 (कि.ग्रा.), कक्षा 3 से 5 के लिए 2-3 (कि.ग्रा.), कक्षा 6 से 7 के लिए 4 (कि.ग्रा.), कक्षा 8 से 9 के लिए 4.5 (कि.ग्रा.) तथा कक्षा 10 के लिए 5 (कि.ग्रा.) निर्धारित है एवं एनसीईआरटी द्वारा नियत पाठ्यपुस्तकों से अधिक पुस्तकें बस्ते में नहीं रहेंगी। स्कूल संचालक/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करना अनिवार्य न किया जाए। स्कूल संचालक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों को पुस्तकें, कृपियां, सम्पूर्ण यूनिफॉर्म आदि सम्बन्धित स्कूल/संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/किताब/संस्था विशेष से क्रय किये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। स्कूल संचालक/प्राचार्य/पालक शिक्षक संघ (पी.टी.एम) सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों के निजी प्रकाशक/मुद्रक/किताब स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करें। स्कूल संचालक/प्राचार्य/किताब स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करें। स्कूल संचालक/प्राचार्य/किताब स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करें। स्कूल संचालक/प्राचार्य/किताब स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं किया जायेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा, यदि किसी विद्यार्थी के



महात्मा फुले की 135वीं पुण्यतिथि मनाई गई

भोपाल। माली समाज में जन्मे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले की 135वीं पुण्यतिथि मध्य प्रदेश संयुक्त माली सैनी मरार समाज एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा फुले चौराहा (7 नंबर बस स्टॉप) भोपाल में मनाई गई। समाज अध्यक्ष जीपी माली (अपर कलेक्टर सेवानिवृत्त) द्वारा माल्यांगण कर श्रद्धांजलि दी। श्री माली ने उनके बताए मार्ग पर चलने एवं समाज उत्थान के कार्य करने पर जोर दिया। इस अवसर पर महात्मा फुले की प्रार्थना की शपथ राजेंद्र अंबाडकर द्वारा दिलवाई गई। कार्यक्रम में हरिसिंह सैनी, दिनेश कुमार सैनी, कृष्ण गोपाल कश्यप, सुखदेव कश्यप, सुनील महाजन, विठ्ठल राव मरखड़े (माली), जगदीश सालंकी, प्रकाश मालवीय, पिकप के संगठन मंत्री पीएस यादव, प्रोफेसर आरजी चौकसे, राम विश्वास कुशवाहा, सुशील घाटोड़, मधु अंबाडकर, वीरेंद्र सैनी, अनिल सैनी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जनकारी महासचिव राजेंद्र अंबाडकर ने दी।

गोंदिया स्टेशन पर काम, बैतूल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द

अप्रैल में गोंडवाना, समता समेत 14 ट्रेनें प्रभावित

बैतूल। अप्रैल माह में ट्रेनें से यात्रा का प्लान बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कार्य के चलते अप्रैल माह में कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसका सीधा असर बैतूल स्टेशन से गुजरने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने इस रूट की



14 ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द करने का निर्णय लिया है। गोंदिया स्टेशन पर लाइन क्रमांक 5 (लेटफार्म 3) के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कारण अप्रैल माह में बैतूल से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित होंगी और कुछ ट्रेनें को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। जिसमें खुरीसाक एक्सप्रेस लगभग 20 दिन निरस्त रहेंगी। ट्रेन 18237 (बिलासपुर-अमृतसर) 5 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026, ट्रेन 18238 (अमृतसर-बिलासपुर) 7 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2026 तक रद्द रहेंगी। वहीं 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को और 12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस-4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को निरस्त रहेंगी। इसी तरह 12807 विशाखापट्टनम-हजरत निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 30 अप्रैल और 12808 हजरत निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस-7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल को निरस्त रहेंगी।

गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गौ प्रतिष्ठ जन जागृति अभियान के समर्थन में धर्मसभा, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। सनातन हिन्दू समाज के तत्वावधान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गो प्रतिष्ठा जन जागृति अभियान के समर्थन में पुराने थाने के पीछे धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर किए गए प्रसंग पर आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे लोग सनातन हिन्दू समाज में जन्म तो लेते हैं। लेकिन हैं विधर्मी। श्री प्रकाश मनमोहन मुद्गल जी हिन्दू संस्कृति आदि पर विस्तृत सारांशित उद्बोधन दिया। कोरिस नेता पुष्पराजसिंह पटेल ने गौ माता पर वोट की राजनीति करने वालों सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे गौ माता के हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। आपने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने दोषारोपण लगाया। हिन्दू समाज शंकराचार्य के अपमान कैसे सहन कर रहे। आपने सभी से एकजुट होकर ऐसे कृत्यों का विरोध करने का आह्वान किया।

समाजसेवी हर्षागोविंद पुर्विया ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ लगाए आरोप निराधार हैं।

रुहून जायसवाल ने कहा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में आरोपी लगा कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधाटा निवासी आशुतोष ब्रह्मचारी, जिस के विरुद्ध 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें सामूहिक बलात्कार, अपहरण, गृहभेदन, मारपीट, गाली-



गलत, गौहत्या तथा शासकीय अधिकारी को रिश्त देने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शंकराचार्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना निन्दनीय है। राहुल जायसवाल ने क.पुन. आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर गौ तस्करी से जुड़े आरोप भी रहे हैं और वह गौमांस से भरे वाहनों की पार्सिंग

कराने के लिए एक एसपी रैंक के अधिकारी को रिश्त देने पहुंचा था। उसे गिरफ्तार किया गया था। आपने आशंका जताई कि शंकराचार्य द्वारा लगातार गौ संरक्षण के लिए आवाज उठाने के कारण गौ तस्करी से प्रभावित लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं। आपने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि ऐसे षड्यंत्रों से बचा

जा सके। इसी अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के साथ रहे महेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस सुरक्षा में होने के उपरांत भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने झूठा प्रकरण में फंसाया है।

धर्मसभा के मंच पर बनखेड़ी के महंत मनमोहन दास महाराज, बाबई के महेंद्र तिवारी, श्री रामकृष्ण दीवान मंदिर के महंत पंडित इंद्रकुमार दीवान, पंकज परसाई, अखिलेश पुरोहित, बलराम श्रोती, यशवंत चौहान, अरविंद पाराशर, विपुलता आवटे, जले शर्मा आदि वक्ताओं कार्यक्रम को संबोधित किया। धर्मसभा के उपाध्यक्ष उपस्थित जनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रियंका भल्लवी को प्रदान किए ज्ञापन में कहा गया है कि जगदगुरु शंकराचार्य प्रभु अविमुक्तेश्वरानन्द के द्वारा चलाए जा रहे गौ प्रतिष्ठा जनजागृति, संरक्षण एवं सुरक्षा अभियान का समर्थन करते हैं। इसी क्रम भारत सरकार गौमाता को राष्ट्रीय पशु गौमाता घोषित करने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक लाकर गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। गौवंश के संरक्षण हेतु देश में गौ मांस के निर्यात पर रोक लगाकर इ प्रतिबंधित किया जाए। तथा गौवंश की तस्करी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करते मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किए जाने का प्रावधान न्याय प्रणाली में किया जाए। जगदगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द के गौ प्रतिष्ठा अभियान से डर कर षड्यंत्रकारियों झूठी शिकायत दर्ज कराई है। उसको शीघ्र रद्द किया जाए।

कृषि विज्ञान मेले में दी उन्नत तकनीक, जैविक खेती सारगर्भित जानकारी दी



सोहागपुर। बनखेड़ी गोविंदनगर में भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि विकास पर परिषदाय विधायक सहित कृषि अधिकारियों ने किसानों को दी गई उन्नत कृषि तकनीक, जैविक व प्राकृतिक खेती की विस्तृत जानकारी दी। उक्त आयोजन आत्मा योजनातन्तर्गत जिला स्तरीय किसान विज्ञान मेला का कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर, बनखेड़ी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सोहागपुर के मनोहर प्रतिक्रम के संचालक सुभाष पटेल ने भी आत्मा योजनातन्तर्गत जिला स्तरीय विज्ञान मेले में अपने कृषि फार्म की उत्पादित वस्तुओं का स्टाल भी लगाया था।

प्रदेश में उपलब्ध हैं आपूर्ति के सभी संसाधन आपूर्ति में नहीं है कोई परेशानी: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विधायक परिस्थितियों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएंगी।



एमपी में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की दिक्कत नहीं: मंत्री चैतन्य काश्यप सीएम ने दिए निगरानी के निर्देश, डीलर एसोसिएशन ने कहा-पाक-बांग्लादेश के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं पैनिक

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर चर्चा के बाद डॉ. मोहन यादव ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। कैबिनेट बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार की जा रही है और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक- मंत्री काश्यप ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के बाद मध्यप्रदेश में सोमवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र के फैसले को

राज्य में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सिस्टम में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और युद्ध के हालातों का प्रदेश पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

सोशल मीडिया से पैनिक फैलने की आशंका

वहीं भोपाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। डीलर्स द्वारा ऑर्डर देने पर नियमित आपूर्ति मिल रही है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर यहां पैनिक की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों को निगरानी रखनी चाहिए, ताकि लोगों में किसी तरह की अफवाह न फैले।

प्रदेश में इतनी है खपत

अजय सिंह के अनुसार मध्यप्रदेश में सालाना करीब 1200 मीट्रिक लीटर पेट्रोल और 1600 मीट्रिक लीटर डीजल की खपत होती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को स्टॉक किया जा सकता है, लेकिन रसोई गैस के मामले में यह संभव नहीं होता, इसलिए उस पर ज्यादा निगरानी जरूरी है।

घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य

इधर रसोई गैस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि आरके गुप्ता ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल बंद है, लेकिन घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मंगलवार शाम चार बजे भोपाल जिला प्रशासन का शांति बैठक प्रस्तावित है, जिसमें स्थिति की समीक्षा कर आगे के निर्णय लिए जा सकते हैं।

शिवराज बोले-ममता दीदी को 'प्रधानमंत्री' के नाम से आपत्ति

● बंगाल में रोकी केंद्र की योजनाएं, जलने वाले जलें, हम किसानों का भाग्य बदलकर रहेंगे

भोपाल (नप्र)। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। शिवराज ने सीधे शब्दों में कहा कि बंगाल की सरकार को जनहित से ज्यादा राजनीति प्यारी है। उन्होंने कहा, विपक्ष तर्कियां लेकर हाथ-हाथ करता रहे, लेकिन दुनिया भारत की कृषि नीतियों की वाह-वाह कर रही है। जलने वाले जला करें, हम किसानों का भाग्य बदलकर ही दम लेंगे।

सदन में जो लोग नारे लगा रहे हैं, उन्होंने बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन तक लागू नहीं किया। उन्हें किसानों के पसीने की कद्र नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को इस धोखे के लिए कभी माफ नहीं करेगी।

नाम की राजनीति- 'प्रधानमंत्री' शब्द से परहेज-शिवराज ने आरोप लगाया कि



पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ इसलिए लागू नहीं की गई क्योंकि उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री जुड़ा है। उन्होंने इसे किसानों के साथ खुला अन्याय और पाप करार दिया।

वोट बैंक बनाम किसान की सेहत- मंत्री ने सदन में कहा कि टीएमसी सरकार को मिट्टी की उर्वरता और जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। प्राकृतिक खेती मिशन को उड़ें बस्ते में डालना इस

बात का सबूत है कि उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना है।

पीएम के नेतृत्व में चीन को पछाड़ा, गांधी भरे-शिवराज ने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश का खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने तंज कसा- एक समय था जब हम अनाज मांगते थे, आज चिंता यह है कि रिकॉर्ड पैदावार को रखें कहां!

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन, अंडरग्राउंड सुरंग बनाने के लिए उतरी जमीन छेदने वाली भारी-भरकम मशीनें

भोपाल। मेट्रो के ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट ने एक बड़ी छलांग लगाई है। करोड़ों से AIIMS के बीच बन रही इस लाइन के सबसे चुनौतीपूर्ण अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई के लिए भारी-भरकम टनल बोरिंग मशीनें यानी TBM तैनात कर दी गई हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट का यह हिस्सा सबसे पेचीदा माना जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन, नादा बस स्टैंड और पुल बोधदा जैसे घने बसे इलाकों के नीचे सुरंग बनाना किसी अभिनयपरीक्षा से कम नहीं है। MPMRCL के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि TBM मशीनों को लॉन्च शाफ्ट में उतारा जा चुका है। ये मशीनें एक साथ दो टनल तैयार करेंगी, ताकि यात्रियों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए। इंजीनियरों के मुताबिक, जमीन के नीचे की मिट्टी और पानी का रिसाव बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन आधुनिक TBM तकनीक को इसी तरह की बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है।

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा...4 युवकों की मौत

कार सवार 5 लोगों की भी हालत नाजुक कटनी के नेशनल हाईवे 43 पर हादसा



कटनी (नप्र)। कटनी में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बड़वारा थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11.30 बजे नेशनल हाईवे- 43 पर हुआ। पुलिस के अनुसार, बाइक सवार चार युवक कटनी से उमरिया की ओर जा रहे थे।

जगतपुर उमरिया गांव के पास चानही मोड़ पर विपरीत दिशा (उमरिया) से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह चकनाचूर हो गई।

कार ने 50 मीटर से ज्यादा घसीटा- घटनास्थल की जांच करते हुए पुलिसकर्मियों और मौजूद लोगों ने बताया कि कार और बाइक की दूरी के साथ सड़क पर घसीटे जाने के निशानों से पता चलता है कि कार ने बाइक सवारों को करीब 50 फीट तक घसीटा है। वहीं कार से भी 20 मीटर दूर पर क्षतिग्रस्त बाइक

मिली है। हादसे के बाद एक घंटा जाम रहा हाईवे- टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर जमा हो गए। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर एक घंटे तक जाम लग गया। सूचना मिलते ही बड़वारा थाना पुलिस और 108 इमरजेंसी वाहन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चारों बाइक सवारों को मृत घोषित कर दिया।

महाराष्ट्र से काम कर लौटे थे तीन साथी- मृतकों की पहचान धीरेंद्र सिंह (18), रामकिशोर सिंह (26), रामदास सिंह (18) और इंद्रभान सिंह (25) के रूप में हुई है, जो उमरिया के मानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। परिजनों के अनुसार, रामकिशोर, रामदास और इंद्रभान सोमवार को ही महाराष्ट्र से मजदूरी कर वापस लौटे थे।

प्रदेश में 'लू' जैसी तपिश, उज्जैन-ग्वालियर-चंबल में चढ़ा पारा

टेम्पेचर सामान्य से 4.63 डिग्री ज्यादा ; दिन में तेज धूप, रात में रहेगी ठंडक

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में इन दिनों दो तरह का मौसम है। दिन इतने गर्म हैं कि पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि रात और सुबह ठंडक है। एक्सपर्ट के मुताबिक, ये मौसम लोगों की सेहत भी बिगाड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, एलर्जी के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में दिन में लू जैसी तपन रही। मंगलवार को भी तेज गर्मी थी।

मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मार्च में पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्मी है। भोपाल, इंदौर, रीवा-शहडोल संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 से 2.7 डिग्री तक ज्यादा है। वहीं, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम



में पारा 3.1 से 4.6 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। आधे से ज्यादा हिस्से में दिन का तापमान 35 डिग्री या इससे अधिक है।

ग्वालियर-उज्जैन में पारा 37 डिग्री के पार, रतलाम सबसे गर्म- प्रदेश में मार्च के पहले पखवाड़े में ही दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सोमवार को रतलाम में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। खजुराहो, धार, गुना, दमोह, सागर, श्यांपुर और मंडला में तापमान 38 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। वहीं, 5 बड़े शहरों में ग्वालियर और उज्जैन सबसे गर्म रहे। यहां तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में 36.8 डिग्री, इंदौर में 36.4 डिग्री और जबलपुर में 36 डिग्री रहा।

एमपी में 'वर्किंग एज' में हो रही मौत

हर साल 60 हजार से ज्यादा मजदूरों की मौतें, अब कलेक्टरों को 5 पॉइंट पर मिले निर्देश

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 60 साल से कम उम्र के मजदूरों की मौत के आंकड़ों ने सरकार की नौद उड़ा दी है। श्रम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में हर साल औसतन 60,000 से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों की मौत हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में औसत आयु करीब 67 वर्ष है, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर अपनी कार्यशील आयु (18 से 60 वर्ष) के दौरान ही दम तोड़ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर 'निवारक स्वास्थ्य उपायों' और जागरूकता के लिए 5 सूत्रीय कड़े निर्देश जारी किए हैं। 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि संबल योजना के तहत बड़ी



संख्या में श्रमिकों की मौतों के बाद परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। **संबल योजना- पारदर्शिता के लिए नया कदम-** विभाग ने निर्देश दिया है कि अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु लाभ) के तहत स्वीकृत किए

गए मामलों की जानकारी अब अनिवार्य रूप से ग्राम और वार्ड सभा की विषय सूची में शामिल की जाएगी। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा सकेगा।

सास-बहू से देवरानी-जेठानी तक: रिश्तों की साझेदारी से खिल रहा ग्रामीण पर्यटन

भोपाल (नप्र)। सास-बहू, मां-बेटी या देवरानी-जेठानी के रिश्तों को अक्सर तकरार और मतभेद के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम इन धारणाओं को बदलते हुए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। जिले के गांवों की महिलाएं आपसी सहयोग और विश्वास के साथ होम-स्टे चला रही हैं और रिश्तों की मजबूती को तस्वीरों की नई राह में बदल रही हैं।

पर्यटन ग्राम धूसवानी की श्रीमती मनेशी धुर्वे और श्रीमती अलका धुर्वे रिश्ते में सास-बहू हैं, लेकिन जब उनके होम-स्टे में पर्यटक आते हैं तो दोनों मिलकर पूरे उत्साह से मेहमाननवाजी में जुट जाती हैं। इसी तरह सासवानी में श्रीमती मालती यदुवंशी अपनी सास श्रीमती शारदा यदुवंशी के साथ मिलकर होम-स्टे का संचालन कर रही हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे जिले में उभरती एक नई सामाजिक



और आर्थिक तस्वीर है, जहां रिश्तों की साझेदारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।

रिश्तों की साझेदारी से मिली पहचान- छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्रामों में चल रहे होम-स्टे केवल आय का साधन नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास का भी प्रतीक बन चुके हैं। यहां सास-बहू, मां-बेटी और देवरानी-जेठानी मिलकर पर्यटकों का

स्वागत करती हैं, भोजन तैयार करती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इन रिश्तों की सामूहिक ताकत ने यह साबित किया है कि जब परिवार की महिलाएं साथ मिलकर काम करती हैं, तो घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है।

जिले में 50 से अधिक होम-स्टे- मध्यप्रदेश में सर्वाधिक होम-स्टे संचालित करने वाले जिलों में शामिल

छिंदवाड़ा में इस समय 50 से अधिक होम-स्टे संचालित हैं। खास बात यह है कि इन सभी होम-स्टे का पंजीयन महिलाओं के नाम पर किया गया है और संचालन की अधिकांश जिम्मेदारी भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। सासवानी, चोपना, काजरा, देवगढ़, चिमटीपुर, गुमतरा और धूसवानी जैसे पर्यटन ग्रामों में स्थानीय महिलाएं पारंपरिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

स्थानीय स्वाद और संस्कृति से जुड़ते पर्यटक- गांव की महिलाएं पर्यटकों के लिए पारंपरिक और स्वादिष्ट स्थानीय तैयार करती हैं। इसके साथ ही वे लोकनृत्य और लोक गायन से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी पर्यटकों को परिचित कराती हैं। इससे पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है, वहीं महिलाओं को आय का सम्मानजनक साधन भी प्राप्त हो रहा है।

महिलाओं के हाथों में होम-स्टे की कमान

गांव की महिलाएं स्वयं होम-स्टे का संचालन कर रही हैं। पर्यटकों के स्वागत से लेकर भोजन व्यवस्था, आवास और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रबंधन तक की पूरी जिम्मेदारी वे ही निभाती हैं। इस पहल ने यह साबित कर दिया है कि सास-बहू, देवरानी-जेठानी जैसे रिश्ते केवल पारिवारिक संबंध ही नहीं, बल्कि सहयोग और विश्वास के मजबूत आधार भी बन सकते हैं। यही साझेदारी आज छिंदवाड़ा के ग्रामीण पर्यटन को नई पहलवट दे रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बन रही है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि होम-स्टे की यह पहल गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यटन ग्रामों की पहचान भी तेजी से बढ़ा रही है। आने वाले समय में यहां पर्यटन गतिविधियों के और विस्तार की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं।

नवजातों के लिए 'पहला टीका' बनेगा मां का दूध

सेंट्रल इंडिया में भोपाल अकेला शहर जहां 3 सरकारी ह्यूमन मिलक बैंक, हमीदिया अस्पताल में इसी महीने शुरू

भोपाल (नप्र)। नवजात शिशु के लिए मां का दूध किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीबायोटिक्स को शुरुआती संक्रमणों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार बीमारी या अन्य कारणों से मां अपने नवजात को स्तनपान नहीं करा पाती। ऐसे में बच्चों को वैकल्पिक दूध देना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए राजधानी भोपाल में ह्यूमन मिलक बैंक की सुविधा को विस्तार दिया जा रहा है। एम्स और जेपी

भोपाल में होंगे तीन सरकारी ह्यूमन मिलक बैंक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 2018 में भोपाल और इंदौर में ह्यूमन मिलक बैंक शुरू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि शुरुआत केवल भोपाल के जेपी अस्पताल में ही हो सकी।

इसके बाद एम्स भोपाल में भी यह सुविधा शुरू की गई। अब हमीदिया अस्पताल में मिलक बैंक शुरू होने के साथ राजधानी भोपाल देश का ऐसा शहर बन जाएगा जहां तीन सरकारी अस्पतालों में ह्यूमन मिलक बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे नवजातों की देखभाल और पोषण व्यवस्था और मजबूत होगी।

सुलतानियां अस्पताल के शिफ्ट होने के बाद बनी योजना

दरअसल, सुलतानियां अस्पताल को हमीदिया परिसर में स्थानांतरित किए जाने के बाद यहां नवजात और मातृत्व सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमीदिया अस्पताल में ह्यूमन मिलक बैंक शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल में आईवीएफ यानी ट्रेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू करने की भी योजना है।



अस्पताल के बाद अब हमीदिया अस्पताल में भी ह्यूमन मिलक बैंक शुरू होने जा रहा है। हमीदिया अस्पताल में यह नई सुविधा शुरू करने की टेंटेटिव डेट 17 मार्च तय की गई है। इसके अनुसार ही तैयारियां चल रही हैं। इसके शुरू होते ही भोपाल देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होगा जहां तीन सरकारी ह्यूमन मिलक बैंक उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया का अकेला शहर होगा, जहां तीन सरकारी ह्यूमन मिलक बैंक होंगे।

हमीदिया अस्पताल में जल्द शुरू होगी नई सुविधा

राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ह्यूमन मिलक बैंक शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां सिल्विल वर्क-तेजी से चल रहा है और आगे लगभग 10 दिनों में इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद आवश्यक मशीनें और उपकरण स्थापित कर मिलक बैंक को शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मार्च माह के भीतर इस सुविधा को शुरू करने की योजना है, जिससे नवजात शिशुओं को समय पर मां के दूध का लाभ मिल सकेगा।